

भोपाल में भाजपा सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी एबीवीपी, एमएलबी कॉलेज के पास से शराब दुकान को हटाने की मांग

भोपाल। छात्राओं की सुरक्षा और शिक्षण संस्थानों के आसपास के माहौल को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने मंगलवार को राजधानी के पॉलिटेक्निक चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सड़क पर उतरीं। महारानी लक्ष्मीबाई (एमएलबी) गर्ल्स कॉलेज के समीप संचालित शराब दुकान को तत्काल हटाने की मांग की।

शिक्षा संस्थान के पास शराब दुकान का विरोध

प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि छात्राओं के कॉलेज के निकट शराब दुकान का संचालन सुरक्षा और सामाजिक वातावरण दोनों दृष्टि से अनुचित है। विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी



की और विभिन्न पोस्टरों के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया। पोस्टरों पर 'शिक्षा के मंदिर के पास शराब की दुकान नहीं चलेगी' और 'जहां ज्ञान की ज्योति जलती है, वहां शराब की दुकान नहीं चलती' जैसे संदेश लिखे गए थे।

परिषद का आरोप है कि कॉलेज के पास शराब दुकान संचालित होने से छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इस वजह से इलाके में असामाजिक तत्वों की आवाजाही बढ़ गई है, जिससे छात्राओं को रोजाना

आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर कॉलेज कैंपस और पास के बस स्टॉप के आसपास छेड़छाड़ की घटनाओं का डर बढ़ गया है।

बैरिकेडिंग पर चढ़े छात्र, पुलिस रही सतर्क

प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्र पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स पर चढ़कर विरोध जताते नजर आए। हालांकि स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

200 से अधिक पुलिसकर्मी और वाटर कैन्नन तैनात

प्रशासन ने एहतियात के तौर पर करीब 200 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी

भी मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा राइट कंट्रोल व्हीकल और वाटर कैन्नन की व्यवस्था भी की गई थी।

कलेक्टर ने दिया सात दिन में समाधान का आश्वासन

प्रदर्शन के बीच भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत की। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि मामले का परीक्षण कर सात दिनों के भीतर उचित समाधान निकाला जाएगा। कलेक्टर के आश्वासन के बाद छात्रों ने अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने पर संतोष व्यक्त किया। छात्र संगठनों का कहना है कि यदि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं हुई तो आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।

सिंहस्थ के लिए उज्जैन में खुलेगा मेला कार्यालय



भोपाल। 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए उज्जैन में मेला कार्यालय खोला जाएगा। इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। उसके साथ ही किसानों को बिना व्याज के अल्पावधि कृषि ऋण जारी

रखने के साथ खरीफ सीजन का ऋण चुकाने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय दिया था। उसकी राशि की भरपाई सहकारी बैंकों को सरकार करेगी इसके अलावा बैठक में अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद निवेश के प्रस्तावों पर निर्णय लेने वाली मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक भी हो सकती है।

जल्द मेट्रो नेटवर्क से जुड़ेगा पुराना भोपाल, 24 मीटर जमीन के नीचे तेजी से बन रही सुरंग

भोपाल। भोपाल मेट्रो के भूमिगत कॉरिडोर के निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। पुराने भोपाल को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने के लिए जमीन के नीचे टनल बनाने का काम अब दोगुने तालमेल के साथ चल रहा है। पहले चरण में भोपाल रेलवे स्टेशन से लेकर पतारा पुल तक 400 मीटर लंबी टिवन टनल बनाई जा रही है। इसके लिए अब दूसरी टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) ने भी खोदाई का काम शुरू कर दिया है।

मेट्रो प्रबंधन काम को लेकर बेहद सतर्क

तकनीकी योजना के अनुसार जब पहली टीबीएम जमीन के नीचे 50 मीटर खोदाई कर आगे बढ़ गई, उसके ठीक बाद दूसरी टीबीएम से टनल बनाने का काम



शुरू किया गया। महज 10 दिन पहले शुरू हुए इस काम में नई मशीन ने अब तक करीब 30 मीटर सुरंग तैयार कर ली है। बांटे 30 मार्च को 24 मीटर की गहराई में उतारी गई पहली टीबीएम अब तक 190 मीटर तक खोदाई पूरी कर चुकी है। चूंकि इस समय शहर में वर्षा का सीजन चल रहा है, इसलिए 24

मीटर की गहराई में हो रहे इस काम को लेकर मेट्रो प्रबंधन बेहद सतर्क है।

तीन महीने का और समय लगेगा

मिट्टी धंसने या पानी के रिसाव जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बेहद सावधानी से टनलिंग का काम आगे बढ़ाया जा रहा है।

अधिकारियों के मुताबिक पहले चरण के इस टनल कार्य को पूरा होने में कम से कम तीन महीने का समय और लगेगा। इसके बाद भूमिगत कारिडोर के दूसरे चरण का काम शुरू किया जाएगा।

करौंद तक चलेगी मेट्रो

पैकेज बीएच-04 के तहत ऑरेंज लाइन के इस भूमिगत कॉरिडोर की कुल लंबाई 3.39 किमी है, जो पातरा पुल से सिंधी कालोनी तक बनेगा। इसमें भोपाल रेलवे स्टेशन और नादरा बस स्टैंड के रूप में दो अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। बता दें कि एम्स से सुभाष नगर तक के रूट पर मेट्रो पहले से ही चल रही है। शेष आठ स्टेशनों और ट्रैक का काम पूरा कर वर्ष 2028 तक करौंद चौराहे तक मेट्रो संचालन का लक्ष्य रखा है।

पॉलिटेक्निक, आकाशवाणी और किलोल पार्क चौराहा प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित, धरना-प्रदर्शनों पर लगी रोक

भोपाल। भोपाल शहर के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण मार्गों में से एक पॉलिटेक्निक चौराहा और उसके आस-पास के क्षेत्रों में अब किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, हड़ताल या पुतला दहन कार्यक्रमों के आयोजन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। नगरीय पुलिस भोपाल के पुलिस आयुक्त संजय कुमार (भा.पु.से.) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 22 जून 2026 से आगामी 02 माह



तक प्रभावी रहेगा। समय के अभाव और स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

की धारा 163 (2) के तहत एकपक्षीय पारित किया गया है। इस आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत पुलिस आयुक्त के समक्ष आवेदन कर सकता है। उनकी संतुष्टि होने पर ही किन्हीं विशेष शर्तों के साथ इस प्रतिबंध से छूट दी जा सकेगी। इस आदेश की प्रतिलिपियाँ भोपाल संभाग के आयुक्त, जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और सभी थाना प्रभारियों सहित संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई और निगरानी के लिए भेज दी गई हैं।

भोपाल एयरपोर्ट के टैक्सी चालकों की हड़ताल स्थगित

भोपाल। भोपाल एयरपोर्ट के ऑनलाइन टैक्सी चालकों की 23, 24 और 25 जून को प्रस्तावित हड़ताल स्थगित कर दी गई है। टैक्सी चालकों ने एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया था। उनका दावा था कि किसी भी ऑनलाइन बुकिंग को स्वीकार नहीं करेंगे।

हालांकि, सोमवार रात भोपाल टैक्सी चालक संघ (भारतीय मजदूर संघ सम्बद्ध) ने बताया कि धरना-प्रदर्शन की अनुमति रद्द कर दी गई है। संगठन का कहना है कि 23, 24 और 25 जून को एयरपोर्ट गांधी नगर क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी गई थी, लेकिन प्रशासन और गांधी नगर थाना ने वीवीआईपी मूवमेंट का हवाला देकर इसे निरस्त कर दिया। संघ ने इसे गरीब ड्राइवर्स की आवाज दवाने की कोशिश बताते हुए कहा कि उनकी हमेशा से नीति रही है कि किसी भी आंदोलन को नियमों के तहत और अनुमति लेकर ही किया जाए। संगठन ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं फैलाना चाहता, बल्कि अपने हक की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ रहा है। संघ ने चेतावनी दी है कि वह जल्द ही दोबारा अनुमति लेकर एग्रीगेटर कंपनियों के विरोध में और उग्र आंदोलन करेगा। संघ के महामंत्री राजेश कुमार नागले ने बताया कि इससे पहले 7 फरवरी और 12 जून को बोर्ड



ऑफिस चौराहे पर सांकेतिक धरना देकर शासन-प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यह कदम ड्राइवर्स को आजीविका बचाने के लिए जरूरी हो गया है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही मांगें नहीं मानी गईं तो शहर में टैक्सी और ऑटो सेवाएं पूरी तरह ठप कर दी जाएंगी, जिससे आमजन को और अधिक परेशानी उठानी पड़ सकती है।

संघ ने स्पष्ट किया है कि उनका मुख्य मुद्दा सरकार द्वारा तय किराए को लागू कराना है। आरोप है कि एग्रीगेटर कंपनियाँ एक प्रावधान का हवाला देकर निर्धारित दर से भी कम यात्रा कर रहे सफर अप्रैल 2026 के आंकड़ों के अनुसार एयरपोर्ट से कुल 1,38,060 से अधिक यात्री यात्रा कर रहे हैं।

ट्रांसफर चाहिए तो मैरिज सर्टिफिकेट लाओ, स्कूल शिक्षा विभाग की नई शर्त से टीचर परेशान

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग की ऑनलाइन स्वैच्छिक तबादला नीति शिक्षकों के लिए राहत के बजाय परेशानी बनती जा रही है। तबादला पोर्टल में कई तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं, जिससे हजारों शिक्षक आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी पति-पत्नी के आधार पर तबादला चाहने वाले शिक्षकों को हो रही है। शिक्षकों का कहना है कि तबादला नीति में कहीं भी मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं बताया गया था। इसके बावजूद पोर्टल पर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अपलोड करने की शर्त आ रही है। कई शिक्षकों के पास यह दस्तावेज नहीं है, क्योंकि इसकी पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी। आवेदन की अंतिम तारीख 24 जून होने से उनकी चिंता और बढ़ गई है। शासकीय शिक्षक संगठन का कहना है कि 90 प्रतिशत ई-अप्लॉड्स की अनिवार्यता,



जनगणना ड्यूटी में लगे शिक्षकों पर रोक और तीन साल की सेवा अवधि जैसी शर्तों के कारण पहले ही बड़ी संख्या में शिक्षक तबादला प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। अब पोर्टल की तकनीकी समस्याओं ने बाकी शिक्षकों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। रामप्रकाश सिंह और उनकी पत्नी

दोनों सरकारी कर्मचारी हैं। वे पति-पत्नी आधार पर तबादला चाहते हैं, लेकिन पोर्टल पर मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। उनका कहना है कि सर्विस बुक में पति-पत्नी की पूरी जानकारी दर्ज रहती है, फिर अलग से विवाह प्रमाण पत्र मांगने का औचित्य क्या है।

जबलपुर के प्राथमिक शिक्षक दीपक शरणागत पारस्परिक तबादला (म्यूचुअल ट्रांसफर) करना चाहते हैं। लेकिन, जिन शिक्षक के साथ वे तबादला करना चाहते हैं, उनका नाम पोर्टल पर नहीं आ रहा। इससे उनका आवेदन पूरा नहीं हो पा रहा है।

आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग

शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने मांग की है कि पोर्टल की तकनीकी खामियां तुरंत दूर की जाएं। साथ ही आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाई जाए, ताकि सभी पात्र शिक्षकों को आवेदन का अवसर मिल सके। संगठन का कहना है कि समस्याएं समय पर नहीं सुलझीं तो बड़ी संख्या में शिक्षक तबादला प्रक्रिया से बाहर रह जाएंगे।

भोपाल के वेस्टर्न बायपास को साधिकार समिति की मंजूरी

भोपाल। वेस्टर्न बायपास को राज्य स्तरीय साधिकार समिति की मंजूरी मिल गई है। मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में हुई एसएलईसी की मीटिंग में वेस्टर्न बायपास को मंजूरी दी गई। अब यह कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाएगा। इस फोरलेन बायपास की लंबाई 41 किमी प्रस्तावित थी। अब इसे 35.61 किमी कर दिया गया है। यह नया मार्ग भोपाल-नर्मदापुरम रोड पर मंडीदीप के पास से शुरू होगा और कोलार, रातीबढ़ होते हुए इंदौर मार्ग पर फंदा कला के पास जाकर जुड़ेगा। इस बायपास के बनने से जबलपुर और नर्मदापुरम की ओर से आने वाला



ट्रैफिक शहर के भीतर प्रवेश किए बिना सीधे इंदौर रोड की तरफ निकल जाएगा, जिससे वाहन चालकों का करीब 1 घंटा समय और

23 किमी की दूरी बचेगी। करीब 2900 करोड़ रुपए लागत आएगी। जानकारी के अनुसार, प्रोजेक्ट को दस लेन के हिसाब से बनाया जा रहा है। इसमें से सिक्स लेन के स्ट्रक्चर पर फोर-लेन बनेगा। साथ ही इसके दोनों तरफ 2-लेन की सर्विस रोड भी बनेगी। इस पर एक रेलवे ओवर ब्रिज, दो फ्लाईओवर, 15 अंडर पास और दो बड़े जंक्शन बनेंगे। प्रोजेक्ट हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर बनेगा। इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट की 40 प्रतिशत राशि पांच किश्तों में दी जाएगी। शेष 60 फीसदी राशि सड़क बनने के बाद 15 वर्षों तक मिलेगी।

आईआरसीटीसी के सीएमडी संजय जैन ने सोने और चांदी की कीमत में गिरावट दिया इस्तीफा, सरकार ने मंजूर भी किया

नई दिल्ली। रेल मंत्रालय की कंपनी इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की तरफ से बड़ी खबर आई है। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार जैन ने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा सरकार ने मंजूर कर लिया है। वह 20.07.2026 को अपने पद से मुक्त हो जाएंगे।

इस्तीफा लिया गया?

रेलवे बोर्ड के गलियारों में ऐसी



अफवाहें उड़ रही है कि संजय जैन से जबरन इस्तीफा लिया गया है। यह खबर पिछले महीने ही आई थी कि उन्हें कुछ ऐसा करने

को कहा गया जो उन्हें स्वीकार्य नहीं था। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा देना उचित समझा। अब खबर आई कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है।

संजय जैन का टर्म 31 दिसंबर 2026 तक के लिए था। लेकिन अब उनका इस्तीफा स्वीकार हो चुका है तो उन्हें समय से पहले ही ऑफिस से निकलना होगा। भारतीय रेल यातायात सेवा में 1990 बैच के अधिकारी जैन इस पद से आने से

पहले उत्तर रेलवे में प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर के पद पर तैनात थे। वह क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं।

बिहार में भागलपुर के हैं

संजय जैन बिहार में भागलपुर के हैं। उनके पिता भागलपुर के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई भागलपुर से ही हुई है। सीए की पढ़ाई के लिए वह कुछ साल तक कोलकाता में भी रहे हैं।



कीमती धातुओं की मांग प्रभावित हुई है। इसके साथ ही निवेशक अमेरिका-ईरान शांति वार्ता और अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर आने वाले बदलावों पर करीब से नजर रख रहे हैं। इसी को लेकर इन धातुओं में गिरावट आई। मंगलवार को एमसीएक्स पर अगस्त

डिलीवरी वाले सोने की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। सोमवार को यह प्रति 10 ग्राम 1,48,118 रुपये पर बंद हुआ था। सुबह 10 बजे यह प्रति 10 ग्राम 1349 रुपये गिरकर 1,46,769 रुपये पर कारोबार कर रहा था। अभी तक के कारोबार में सोना 1590 रुपये टूट चुका था।

न्यूज़ ब्रीफ

यूएस की मिली छूट तो तीन फीसदी से ज्यादा सस्ता हुआ क्रूड



नई दिल्ली। स्विटजरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत के बीच अमेरिका की तरफ से बड़ी घोषणा हुई है। अमेरिका ने ईरानी क्रूड खरीदने पर दो महीने की छूट दे दी। इसके बाद आज सुबह स्टैंडर्ड माने जाने वाले ब्रेंट क्रूड के दाम में तीन फीसदी से ज्यादा गिरावट दिखाई है। हालांकि, भारत में पेट्रोल-डीजल बेचने वाली सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार, 23 जून 2026 को भी दाम में कोई बदलाव नहीं किया। अपने यहां बीते 25 मई के बाद दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

पिछले महीने 4 बार बढ़े हैं दाम

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव बीतने के बाद ही पेट्रोलियम कंपनियों ने बीते मई महीने में चार बार दाम बढ़ा चुकी है। ऐसा महज 11 दिनों में हुआ है। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने सबसे पहले 15 मई 2026 को पेट्रोल 3 रुपये और डीजल 3.29 पैसे महंगा किया था। इसके बाद 19 मई को पेट्रोल 87 पैसे तो डीजल 91 पैसे, 23 मई 2026 को पेट्रोल 87 पैसे तो डीजल 91 पैसे और 25 मई 2026 को पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये महंगा किया था। उसके बाद दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

4 महानगरों में पेट्रोल का दाम

तेल कंपनियों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में आज पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। कोलकाता में इसकी कीमत 113.51 रुपये, मुंबई में 111.21 रुपये और चेन्नई में 107.77 रुपये हैं। एक अनुमान के मुताबिक क्रूड ऑयल महंगा होने से सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और जेट फ्यूल पर करीब 750 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है।

डीजल की कीमत क्या है

सरकारी ऑयल कंपनियों के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में डीजल का प्रति लीटर दाम 95.20 रुपये है। कोलकाता में यह 99.02 रुपये, मुंबई में 97.83 रुपये और चेन्नई में 99.55 रुपये प्रति लीटर है। कच्चे तेल की कीमत में हाल में काफी बढ़ोतरी हुई है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद यह करीब 50 फीसदी महंगा हो गया है।

पेट्रोल-डीजल का कब घटेगा दाम?

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बीते शनिवार को संकेत दिया था कि कम कीमत पर खरीदा गया कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरियों तक पहुंचता है, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुरी ने कहा था कि तेल विपणन कंपनियां (हफ्छह) वर्तमान में ऊंचे दामों पर खरीदे गए कच्चे तेल को प्रोसेस कर रही हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी का फायदा खुदरा कीमतों में दिखने में थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने बताया था कि फिलहाल कंपनियों के पास महंगे दामों पर खरीदे गए कच्चे तेल का स्टॉक है। जब कम कीमत पर खरीदा गया क्रूड उनके पास पहुंचेगा, तो ईंधन की कीमतों में कमी आने की संभावना है।

भारतीय कंपनियों को अभी भी नुकसान!

15 जून 2026 को पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया था कि अभी भी सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हर लीटर पेट्रोल की बिक्री पर 30 रुपये और हर लीटर डीजल की बिक्री पर 27 रुपये का घाटा हो रहा है। एक अप्रैल 2026 को इन कंपनियों को पेट्रोल बेचने पर 24 रुपये प्रति लीटर और डीजल बेचने पर 105 रुपये प्रति लीटर का घाटा हो रहा था।

होर्मुज से बंद हुए भारत में एलपीजी के रास्ते तो अमेरिका ने भेजे टैंकर



नई दिल्ली। पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही में आई रुकावटों के बीच भारत ने अपनी रसोई गैस की आपूर्ति बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। रॉयटर्स के मुताबिक भारत की ओर से अमेरिका से आयात की जाने वाली एलपीजी जून महीने में पहली बार 10 लाख मीट्रिक टन के

आंकड़े को पार करने जा रही है। इस महीने भारत द्वारा अमेरिका से 11 लाख से 12 लाख टन एलपीजी आयात किए जाने की उम्मीद है, जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष से पहले भारत अपनी जरूरत का लगभग 90 लाख टन पर पहुंच गया। भारत पहले से ही अमेरिका के साथ अपने व्यापार

लाख टन प्रति महीना था।

ईरान संकट से गिरा आयात

ईरान संकट के कारण अप्रैल में भारत का एलपीजी आयात तेजी से गिरकर 6.96 लाख टन रह गया था। हालांकि, मई में वैकल्पिक स्रोतों से खरीदारी बढ़ने के कारण यह सुधरकर 11.5 लाख टन पर पहुंच गया। भारत पहले से ही अमेरिका के साथ अपने व्यापार

संकट में भी तेल नहीं निकाल पाया भारत, इकोनॉमी को बड़ा झटका

नई दिल्ली। भारत के कोर सेक्टर की विकास दर मई महीने में घटकर सात महीने के निचले स्तर 0.5% (सालाना आधार पर) पर आ गई है। अप्रैल में यह 1.8% थी। सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार एनजी से जुड़ी इंडस्ट्रीज के कमजोर प्रदर्शन के कारण कुल उत्पादन में यह गिरावट दर्ज की गई है। ईरान संकट के बाद भी भारत का कच्चा तेल उत्पादन गिर गया।

पिछले साल यानी मई 2025 में इन आठ कोर सेक्टर की वृद्धि दर 1.2% रही थी। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि पिछले साल के कमजोर आधार के बावजूद विकास दर का कम रहना मुख्य रूप से पेट्रोलियम आधारित क्षेत्र के उत्पादन में आई गिरावट के कारण है। हालांकि बिजली सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखी गई।

पश्चिम एशिया संकट जिम्मेदार

इक्रा (ICRA) के प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट राहुल अग्रवाल ने बताया कि रिफाइनरी उत्पादन में आई इस कमी



के पीछे कुछ हद तक पश्चिम एशिया का संकट जिम्मेदार है। वहीं, सबनवीस के अनुसार, कच्चे तेल के बढ़ते आयात और अंतरराष्ट्रीय बाजार में नरम कीमतों के कारण पेट्रोलियम क्षेत्र प्रभावित हुआ है। कोयला उत्पादन में कमी इसलिए आई क्योंकि कंपनियां अपने स्टॉक को बेहतर तरीके से मैनेज करने और उत्पादन घटाने पर ध्यान दे रही थीं। ये

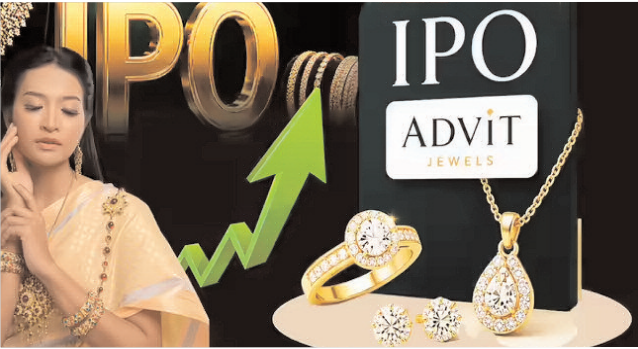
आठ कोर सेक्टर भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में 40.27% का वेटेज रखते हैं। अप्रैल महीने में भारत का औद्योगिक उत्पादन 4.9% की दर से बढ़ा था। मई महीने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने IIP वृद्धि दर 1 से 1.5% रहने का अनुमान जताया है, जबकि इक्रा ने इसके 2 से 3% के बीच रहने की उम्मीद जताई है।

अद्वित ज्वेल्स आईपीओ के जीएमपी में तेजीबड़े मुनाफे की उम्मीद

नई दिल्ली। ज्वैलरी मैनुफैक्चरिंग कंपनी अद्वित ज्वेल्स का आईपीओ मंगलवार 23 जून से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों की लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। आईपीओ के खुलते ही पहले दिन इसे बुक कराने के लिए रिटेल निवेशकों में होड़ मच गई। रिटेल कैटेगिरी में शुरुआती करीब 3 घंटे में यह 4 गुना से ज्यादा भर गया। कंपनी इस आईपीओ के जरिए करीब 165 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। इसके तहत 1.19

करोड़ फ्रेश (नए) शेयर जारी किए जा रहे हैं। रिटेल निवेशक इस आईपीओ को 25 जून तक बुक करा सकेंगे। इसकी लिस्टिंग 1 जुलाई को हो सकती है। इसका प्राइस बैंड 130 से 138 रुपये के बीच है। एक लॉट में 100 शेयर हैं। रिटेल निवेश न्यूनतम 1 और अधिकतम 14 लॉट बुक करा सकता है।

इस कंपनी के आईपीओ ने ग्रे मार्केट में धूम मचाई हुई है। 138 रुपये के आईपीओ प्राइस पर मंगलवार दोपहर 12 बजे इसका ग्रे



मार्केट प्रीमियम 65 रुपये है। यानी इसमें 47 फीसदी की तेजी आ चुकी

है। अगर इसमें इसी प्रकार तेजी बनी रहती है तो यह आईपीओ लिस्टिंग

पेंशन से जुड़ी शिकायत होगी दूर,पीएफ-आरडीए ने लॉन्च किया पेंशन सहायक

नई दिल्ली। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने PFRDA पेंशन सहायक नाम का एक AI-बेस्ड शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसने पहले के सेंट्रल ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम की जगह ली है। इसका मकसद पेंशन सब्सक्राइबर्स के लिए शिकायतें दर्ज करना, इनके स्टेटस को ट्रैक करना और समय पर समाधान पाना आसान बनाना है। यह प्लेटफॉर्म पेंशन से जुड़ी अलग सर्विस सुविधाओं को एक ही डिजिटल सिस्टम में लाता है। यह पोर्टल वेब, मोबाइल और वॉट्सऐप आधारित सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा। यह नया शिकायत सिस्टम 22 भाषाओं में उपलब्ध होगा, जहां यूजर इनमें से किसी भी भाषा में बोलकर वॉक्स कमांड के जरिए शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

पुराने सिस्टम से अलग? पुराना सिस्टम काफी पारंपरिक था जहां यूजर को पेंशन सिस्टम



की तकनीकी जानकारी होनी जरूरी थी। वहीं नया %पेंशन सहायक पूरी तरह से यूजर-फ्रेंडली, AI-चालित और बोलकर काम करने वाला एक आधुनिक इकोसिस्टम है। यहां आपको बस अपनी समस्या बतानी है, बाकी का सारा काम सिस्टम खुद कर देगा।

पेंशन सहायक की बड़ी खूबियां

अब शिकायतों के लिए आपको अपना परामर्श रिययरमेंट अकाउंट नंबर या पासवर्ड याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए तुरंत लॉगिन कर सकते हैं। अगर एक ही मोबाइल नंबर से एक से अधिक ब्रह्म लिंकड हैं, तो लॉगिन करते ही वे सभी

अकाउंट्स एक ही स्क्रीन पर दिखाई दे जाएंगे। अटल पेंशन योजना के वो सब्सक्राइबर्स जो अपना PRAN भूल गए हैं, वे भी इसके जरिए आसानी से अपना नंबर ढूँढ सकते हैं।

भाषिणी इंटीग्रेशन की मदद से यह पोर्टल 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। आप अपनी स्थानीय भाषा में बोलकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। खास बात यह है कि आपको जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा और आप उसे ऑडियो रूप में भी पा सकते हैं। अगर तय समय सीमा के भीतर आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो सिस्टम खुद-ब-खुद उस शिकायत को सीनियर अथॉरिटी के पास भेज देगा। अगर आप पहली बार मिले समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो सिर्फ एक क्लिक में मामले को ओम्बड्समैन या एनपीएस ट्रस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही आप समाधान की क्वालिटी को रेटिंग भी दे सकते हैं।

जयपुर स्थित अद्वित ज्वेल्स रामभजो ब्रांड के तहत हाथ से बने कुंदन, पोलकी, डायमंड व स्टडेड ज्वेलरी बनाती और सप्लाई करती है। कंपनी BwB (डोलर और रीटेलर्स) के साथ-साथ ऑर्डर पर ज्वैलरी बनवाने वाले ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करती है। आईपीओ से मिलने वाली रकम का उपयोग कंपनी अपने कर्ज को चुकाने, वॉकिंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी।

फुटबॉल विश्वकप में नहीं होकर भी हम वहां मौजूद हैं



फुटबॉल विश्व कप में भारतीय टीम भले ही नहीं खेल रही हो, लेकिन वालंटियर्स से लेकर पत्रकारों तक, टूर्नामेंट में भारत की मौजूदगी है। नागपुर के 75 वर्षीय ओम मुंद्रा का ही उदाहरण लें। यह उनका सातवां विश्व कप है और वे न्यूयॉर्क में वालंटियर के रूप में प्रशंसकों को इस प्रतिस्पर्धा के पूरे रोमांच में शामिल करने में मदद कर रहे हैं। उनसे इस बारे में पूछें तो आपको एक जानी-पहचानी मुस्कान मिलेगी। वे कहेंगे, मुझे खेलों से प्यार है और मैं इस रोमांच का हिस्सा बनना चाहता हूं। ओम मुंद्रा अकेले नहीं हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने वर्षों तक केवल इसीलिए पैसे बचाए ताकि विश्वकप देखने अमेरिका पहुंच सकें। दो साल बचत करके विश्वकप देखने आने वाले एक दम्पती ने मुझसे कहा, यहां सब कुछ बहुत महंगा है। बेसिक ट्रांसपोर्ट और खाने-पीने के लिए भी मैच-डे का अनुभव लगभग 30,000 रु. का पड़ता है। फिर भी हम अधिक से अधिक मैच देखने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं।

देखें तो अमेरिका में इन तमाम भारतीयों की मौजूदगी अपने आप में एक कहानी है। यह हमारी सॉफ्ट-पावर का प्रमाण है। यह भारत का दुनिया तक पहुंचना है। अपनी टीम के वहां न होने के बावजूद, हमारे फैन्स और वालंटियर्स ने विश्वकप में भारतीय रंग धोल दिया है। यह केवल मीडिया और वालंटियर्स तक सीमित नहीं है। अमेरिका में आप जहां भी नजर डालेंगे, भारतीय प्रभाव दिखेगा। आप किसी भी स्टेडियम में जाएं, आपको बहुत से लोग हिंदी या बांग्ला बोलते हुए सुनाई देंगे। वास्तव में, विश्वकप के लिए अमेरिका आए लोगों में भारतीय प्रशंसकों की हिस्सेदारी 2 से 3 तक है। कैस्सस सिटी में- जहां अर्जेंटीना का पहला मैच हुआ था और जिसमें लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाई थी- वहां के बंगाली समुदाय ने महीनों पहले से योजना बनानी शुरू कर दी थी, ताकि वे मेसी को खेलते हुए देख सकें। वे फैन पार्कों में लगातार मौजूद रहते हैं और उनके लिए विश्व कप एक महीने तक चलने वाला ऐसा आयोजन है, जिसका वे भरपूर आनंद लेते हैं। वे सभी अपने पेशेवर जीवन में अच्छी तरह से स्थापित लोग हैं। वास्तव में, आप जिस भी खेल आयोजन में जाएंगे, वहां भारतीय प्रशंसकों को लेकर यही स्थिति दिखाई देगी। इस बार के विश्वकप में 48 टीमों शिरकत कर रही हैं। इनमें एशियाई टीमों की भी अच्छी भागीदारी है। ऐसे में हमें यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ प्रयास करने की आवश्यकता है कि आने वाले दशकों में फीफा विश्व कप में भाग लेने का भारत का सपना केवल एक असंभव कल्पना बनकर न रह जाए। भारत के फुटबॉल सिस्टम में पर्याप्त धन मौजूद है और हमें आशावादी तथा उम्मीद से भरे रहने की आवश्यकता है। हां, हमें राष्ट्रीय टीम के लिए अधिक अनुभव, अधिक मैच और मजबूत घरेलू ढांचे की जरूरत है, जो आगे चलकर आईएसएल को भी मजबूती दे। हमें अधिक सक्रिय एआईएफएफ की आवश्यकता है, जो भारत के फुटबॉल सिस्टम की वास्तविक और तात्कालिक समस्याओं को हल करने पर केंद्रित हो। और यहीं पर मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मीडिया में अधिकांश लोग चार साल में एक बार जागत होते हैं और पूछते हैं कि 130 करोड़ की आबादी वाला देश विश्वकप क्यों नहीं खेल रहा, जबकि 5 लाख की आबादी वाला केप वर्ड यूरोपीय चैंपियन स्पेन के खिलाफ एक अंक हासिल करने में सफल रहा। हालांकि यह एक आकर्षक सुर्खी जरूर बनती है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि इनमें से अधिकांश लोग विश्व कप समाप्त होते ही फिर गुम हो जाएंगे और 2030 में ही फिर दिखाई देंगे। हकीकत यह है कि 130 करोड़ में से 129.5 करोड़ लोगों को खेलों के लिए बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। भारतीय खेलों को एक अधिक रचनात्मक और आत्मनिरीक्षण वाले दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो कमियों को पहचाने और आगे बढ़ने का रास्ता तय करे। यदि एआईएफएफ नेतृत्व कर सकता है, तो भारतीय फुटबॉल को आवश्यक गति देने के लिए पर्याप्त धन और जुनून मौजूद है। तब तक हम विश्व कप के लिए पैसे बचाते रहेंगे- कभी फैन्स तो कभी वालंटियर्स के रूप में- और उम्मीद करते रहेंगे कि एक दिन हमें वैश्विक मंच पर भारत के लिए भी चीयर करने का मौका मिलेगा।

युवाओं को नशे से बचाएगी सही जीवनशैली और सजगता

युवाओं में नशीली दवाओं के सेवन की लत गंभीर स्वास्थ्य व सामाजिक समस्या बन गयी है। नशे का लगातार फैलता जाल चिंताजनक है। इसके सेवन, दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ सामाजिक व पारिवारिक मोर्चे पर सजगता जरूरी है। अभिभावकों को चाहिये कि वे किशोरों-युवाओं में इस जानलेवा जाल से बचने की समझ पैदा करें। इसमें भावनात्मक जुड़ाव, संवाद, खेल गतिविधियां और अपनों का संबल खास सहायक है। यूनाइटेड नेशंस द्वारा मनाये जाने वाला सालाना 'ड्रग दिवस' भी यही संदेश देता है।

हर वर्ष 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रेफिकिंग मनाया जाता है। यह दिन विश्व ड्रग दिवस के नाम से भी जाना जाता है। साल 1989 से यूएन द्वारा मनाया जा रहा यह विशेष दिन नशे के खिलाफ जागरूकता लाने और लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए बेहतर परिवेश बनाने का संदेश देता है। सभी और ड्रग फ्री जीवनशैली अपनाने को प्रोत्साहित करता है।

यह दिवस विशेष रूप से नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त दुनिया बनाने की सजगता लाने से जुड़ा है। मन-जीवन ही नहीं परिवार, समाज और देश में भी बिखराव लाने वाले नशे के खिलाफ सामाजिक जागरूकता नहीं पारिवारिक मोर्चे पर भी सजगता आवश्यक है। भावनात्मक जुड़ाव भरी समझाइश और अपनों का संबल भी नई पीढ़ी को इस जीवन लीलने वाली



आदत-लत से बचा सकता है। नशीली दवाओं का सेवन, दुरुपयोग और अवैध तस्करी दुनिया के हर समाज के लिए समस्या बनी हुई है। दुनिया के हर हिस्से में बसे लोग इस समस्या से जुझ रहे हैं। यह नई पीढ़ियों का जीवन सहेजने से जुड़ी सबसे बड़ी चिंता बन गई है। इतना ही नहीं परिवार, समाज और व्यक्तिगत स्तर पर होने वाली बहुत ही दुखद घटनाओं का कारण भी नशे की लत ही है। यही वजह है कि ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रेफिकिंग के खिलाफ जागरूकता आवश्यक है। बच्चों में इस जानलेवा जाल से बचने की समझ पोसना जरूरी है। इस साल का वैश्विक विषय 'विश्व ड्रग समस्या-मौजूदा मुद्दे, नई चुनौतियां, नई प्रतिक्रियाएं' है। यह वैश्विक अभियान दुनिया भर में मादक पदार्थों के उपयोग, अवैध तस्करी से पैदा होने वाली चुनौतियों का समाधान करना और

जनमानस, खासकर युवाओं को सुरक्षित रखने से जुड़ा है। आपराधिक घटनाएं हों या सड़क हादसे, नशे के फेर में पड़कर अपना ही जीवन छीन लेने वाले वाक्ये हों या समाज-परिवार के लिए बोझ बन जाने के हालात- मौजूदा दौर में नशा न केवल एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बल्कि सामाजिक समस्या भी बन गया है।

जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक सेहत पर तो दुष्प्रभाव डालती ही है, सामाजिक माहौल भी दूषित करती है। इससे जुड़े सभी मुद्दों को अच्छे से समझना जरूरी है। इससे जुड़ी चुनौतियों का सामना करने का परिवेश बनाना आवश्यक है। हमारे यहां भी नशे के फैलते जाल और भ्रमित होती युवा पीढ़ी की दिशाहीनता चिंता का विषय बन गई है। स्वस्थ जीवनशैली के लिए मान पाने वाले भारतीय समाज में नशा करने वाले लोगों की तादाद बड़ रही है।

कहीं जाने-अनजाने लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं तो कहीं आधुनिक जीवनशैली के नाम पर नशे की लत का शिकार बन रहे हैं। यही वजह है कि हमारे यहां भी प्रशासनिक, सामाजिक और पारिवारिक, हर स्तर अपर समस्या को संबोधित किया जाना आवश्यक है। गौरतलब है कि हमारे देश में भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 17-26 जून तक जन-जागरूकता लाने से जुड़ी नशा मुक्त भारत मुहिम बेहद अहम है। इसकी थीम 'नशा मुक्त भारत अभियान - विकसित भारत की पहचान' रखी गई है। असल में मन और जीवन को पूरी तरह दिशाहीन करने वाले मादक पदार्थों की लत से घिरते समाज में विकास और बेहतरी के कोई मायने नहीं होते। दुखद है कि बड़े शहरों से लेकर दूर-दराड़ गांवों तक नशे का जाल फैल गया है। ऊर्जावान युवाओं का भविष्य इसकी भेंट चढ़ रहा है। इतना ही नहीं, यह व्यावहारिक आक्रोश से लेकर शारीरिक व्याधियों तक, ड्रग्स नकारात्मकता और हर तरह की शारीरिक-मानसिक परेशानियों की जड़ हैं। ऐसे में हर नागरिक का इस जाल से बचना जरूरी है। वर्ल्ड ड्रग डे की 2026 की थीम 'द वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम- पर्सिस्टिंग इश्यूज, न्यू चैलेंजेस, इनोवेटिव रिसपॉन्स' यही संदेश देती है कि दुनिया का हर देश, हर समाज इस समस्या से संबंधित चैलेंजेज और इश्यूज को सही से समझकर इसका हल निकाले। विशेषकर युवाओं का जीवन बचाने की कोशिशें हरेक

स्तर पर की जाएं। स्वस्थ नागरिक ही परिवार, समाज और राष्ट्र की मजबूत बुनियाद बनाते हैं। वहाँ नशीली चीजों के सेवन की आदत दिल-दिमाग और शरीर सब कुछ कमजोर कर देती है। सोच-समझ छीन लेती है। जीवन को अपराध, हिंसा और अस्थिरता की ओर धकेलती है। नियमित दिनचर्या से दूर ईंसान को ऐसे अंधकार में धकेल देती है, जिसमें जीवन ही अपना अर्थ खो देता है। गिरते स्वास्थ्य से कमाई के रास्ते बंद हो जाते हैं तो दूसरी ओर,परिवार के आर्थिक संकट में घिरने के चलते इलाज ले पाना भी कठिन हो जाता है।

नशे की लत अपनों और खुद के जीवन को चक्रव्यूह में फंसा देती है। इसलिए, परिजन बंद होते बच्चों को खेलों, कला, योग, ध्यान और अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ें। अपने परिवार की जमीनी जीवनशैली वाले रहन-सहन से नियम समझाएं।

सेहत की संभाल को लेकर सजग बनावें। ध्यान रहे कि अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले ईंसान का नशे की ओर झुकाव नहीं होता। परिवार का कोई सदस्य नशे के घेरे में आ जाये तो उससे दूरी बनाने या दुर्यव्यहार करने के बजाय स्नेह-साथ दें। इस जाल से निकलने के लिए भी शारीरिक सक्रियता सबसे ज्यादा मददगार बनती है। अपने स्वास्थ्य की देखभाल की ओर हुआ झुकाव कभी मन को डिगने नहीं देता।

यूपी में योगी सरकार होने के मायने, 2017 के बाद बदली यूपी की तस्वीर

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नौ वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और इतना समय बीत जाने के बाद इस बात का आकलन आवश्यक है कि आखिर जनता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या मायने रखते हैं? वे कौन से कारण हैं जो उन्हें पूर्ववर्ती शासकों से अलग पहचान देते हैं। 2017 से पूर्व के राजनीतिक परिदृश्य का विश्लेषण करें तो, दंगा, दलित उत्पीड़न, सनातन का अपमान और अल्पसंख्यक तुष्टिकरण जैसे मुद्दे प्रमुखता से उभरते हैं. कहा जा सकता है कि 2017 का सत्ता परिवर्तन केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि इसने राज्य की प्रशासनिक पहचान, सुरक्षा व्यवस्था, सांस्कृतिक नीतियों और विकास को एक नई दिशा दी है.

2017 के पहले के उत्तर प्रदेश में वोट की राजनीति चरम पर थी. सांप्रदायिक तुष्टिकरण तत्कालीन सरकार के एजेंडे में शामिल था. एक तरह से राज्य राजनीतिक गुलामी की ओर था. दलितों का उत्पीड़न, अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण, विकास की अनदेखी का दर्श जनता भुगत रही थी. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2014-2016 के बीच अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराधों में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे था. दलित उत्पीड़न एक्क तो इतना निष्प्रभावी था कि



उसका कोई अर्थ ही नहीं रह गया था. मुजफ्फरनगर का दंगा तो राज्य पर ऐसा कलंक है जो शायद ही कभी धोया जा सके. जाने कितने हिंदुओं का पलायन हुआ और जाने कितने लोगों की जमीनें दबंगों ने हथिड़ाई, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी रही. आक्रोश का लावा कभी न कभी फटता ही है और 2017 में लोगों ने इसे अपने मतों से अभिव्यक्त किया. प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 312 सीटें. यह सिर्फ एक राजनीतिक दल को बहुमत ही नहीं था, अपने अपमान से आहत जनता का विद्रोह था. जनता किसी राजनीतिक दल को इस तरह शिरोधार्य करती है तो सरकार से अपेक्षाएं अत्यंत ही गहरी हो जाती हैं. मुख्यमंत्री के रूप में योगी

आदित्यनाथ ने इस चुनौती को समझा और आत्मसात भी किया. पं. दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि जब तक शासन व्यवस्था अपनी सांस्कृतिक आत्मा से विमुक्त रहेगी, तब तक वह लोक-कल्याण का वास्तविक मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकती. राज्य को आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों तक पहुंचना होगा. इससे प्रेरणा लेकर मुख्यमंत्री योगी ने सुशासन को केवल एक प्रशासनिक शब्द नहीं, गुणांतकारी संकल्प के रूप में आगे बढ़ाया. इसमें उन्होंने वीर सावरकर के विचारों को भी जोड़ा जो यह मानते थे कि शक्ति के बिना शांति की स्थापना असंभव है. माफिया व अपराधियों के खिलाफ जीरो टालरेंस इसका उदाहरण है. कानून सबके लिए एक है, योगी का

यह संदेश पूरे प्रदेश में गुंजा. शपथ लेने के तत्काल बाद अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई ने वोट बैंक की राजनीति को पीछे धकेला तो एंटी-रोमियो स्काड के गठन ने बेटीयों को निश्च होकर घर से बाहर निकलने का आत्मबल दिया. माफिया के विरुद्ध अभियान तो शायद राज्य के इतिहास में दर्ज किया जाए. माफिया की कमर टूटने का अर्थ था सर्गाटित अपराध का ख़ात्मा. यानि अब राज्य में व्यापारियों को धमकाकर रंगदारी वसूलने की जुरत कोई नहीं करेगा. जाहिर है कि यह सब एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन नौ साल बीत जाने के बाद बदलाव का यह भाव ही योगी को राज्य के लिए आवश्यक बनाता है. प्रदेश दंगों से मुक्त हुआ. प्रशासन को सीधा संदेश कि दंगाई किसी भी समुदाय के हों, कार्रवाई अनिवार्य है. निषान शक्ति अभियान, महिला हेल्पलाइन, और पुलिस में महिला भर्ती ने उस वातावरण को बदलने की कोशिश की जहां बेटी का बाहर निकलना परिवार की चिंता का सबसे बड़ा कारण होता था. यह कहने की बात नहीं कि निर्भीकता केवल कानून से नहीं आती, उस विश्वास से आती है कि शासन नागरिकों के पक्ष में है और इस सुरक्षित वातावरण ने निवेशकों के लिए जैसे रेड कारपेट बिछा दिया. %बीमार्क% राज्य में गिना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे

बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है. देश ही नहीं विदेश के निवेशक उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और आने को आतुर हैं. गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे ने न केवल दूरियां घटाई, बल्कि उन क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ा जो दशकों से उपेक्षित थे. जेवर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना, डेटा सेंटर नीति, यह नए उत्तर प्रदेश के नक्शे में शामिल करेंगे. जाहिर है कि यह सब एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन नौ साल बीत जाने के बाद बदलाव का यह भाव ही योगी को राज्य के लिए आवश्यक बनाता है. प्रदेश दंगों से मुक्त हुआ. प्रशासन को सीधा संदेश कि दंगाई किसी भी समुदाय के हों, कार्रवाई अनिवार्य है. निषान शक्ति अभियान, महिला हेल्पलाइन, और पुलिस में महिला भर्ती ने उस वातावरण को बदलने की कोशिश की जहां बेटी का बाहर निकलना परिवार की चिंता का सबसे बड़ा कारण होता था. यह कहने की बात नहीं कि निर्भीकता केवल कानून से नहीं आती, उस विश्वास से आती है कि शासन नागरिकों के पक्ष में है और इस सुरक्षित वातावरण ने निवेशकों के लिए जैसे रेड कारपेट बिछा दिया. %बीमार्क% राज्य में गिना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे

चुनौतियों के साथ अवसरों का भी दौर

भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां चुनौतियां भी हैं और अवसर भी। एक ओर खुदरा महंगाई दर रिजर्व बैंक के लक्ष्य से नीचे बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर थोक महंगाई में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। हाल के भू-राजनीतिक तनावों में कमी के बाद रुपया फिर मजबूती की ओर बढ़ा है, देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है और भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। यह तस्वीर आश्चस्त करने वाली है, पर इसके भीतर कुछ ऐसे संकेत भी छिपे हैं, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण संकेत थोक और खुदरा माहंगाई के बीच बढ़ता अंतर है। हाल में थोक महंगाई तेजी से बढ़ी है, जबकि खुदरा महंगाई अपेक्षाकृत नियंत्रित रही है। यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहती। उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि का बोझ अंततः उपभोक्ताओं तक पहुंचता ही है। इसलिए आज जो दबाव उद्योगों और उत्पादकों पर दिखाई दे रहा है, उसका असर आने वाले समय में आम उपभोक्ता की जेब पर भी पड़ सकता है। थोक महंगाई मुख्यतः उन लागतों को दर्शाती है, जिनका सामना उत्पादकों को करना पड़ता है। जब ऊर्जा, परिवहन, आयातित कच्चे माल और विनिर्माण की लागत बढ़ती है, तब कंपनियां शुरुआत में अपने मुनाफे में



कटौती करके कुछ बोझ स्वयं वहन करती हैं, पर यदि लागत का दबाव बना रहता है तो अंततः कीमतों में वृद्धि करनी पड़ती है। थोक महंगाई में हाल की तेजी को केवल एक अस्थायी घटना मानना उचित नहीं होगा। इस बढोतरी का एक बड़ा कारण ऊर्जा लागत है। वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ईंधन और बिजली की ऊँची कीमतों ने उत्पादन लागत को बढ़ाया है। सकारात्मक पक्ष यह है कि पश्चिम एशिया में तनाव कम होने से वैश्विक तेल कीमतों में नरमी आई है। भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए यह राहत के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक

अवसर भी है। अक्सर कम तेल कीमतों को अतिरिक्त खर्च करने का अवसर समझ लिया जाता है, पर यह दृष्टिकोण दूरदर्शी नहीं होगा। बाजारों के उतार-चढ़ाव स्थायी नहीं होते। समझदारी इसी में है कि अनुकूल परिस्थितियों का उपयोग आर्थिक बुनियाद को मजबूत करने में किया जाए। सबसे पहले घटी तेल कीमतों से होने वाले लाभ का उपयोग बाहरी क्षेत्र की मजबूती के लिए किया जाना चाहिए। जब तेल आयात बिल घटता है तो चालू खाते का संतुलन बेहतर होता है। इस अवसर का उपयोग विदेशी मुद्रा भंडार को और मजबूत करने में किया जा सकता है। मजबूत भंडार केवल आर्थिक शक्ति का

प्रतीक नहीं होते, बल्कि भविष्य के वैश्विक झटकों के खिलाफ सुरक्षा कवच भी प्रदान करते हैं। दूसरा, यह ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का उपयुक्त समय है। पिछले एक दशक में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रत्येक नई प्रगति भारत की आयातित ऊर्जा पर निर्भरता को कम करेगी। यह पर्यावरण संरक्षण संग आर्थिक सुरक्षा का भी प्रश्न है। तीसरा, कम ऊर्जा लागत भारत के निर्यात क्षेत्र के लिए भी अवसर लेकर आई है। दुलाई खर्च घटने से भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। लक्ष्य निर्यात बढ़ाने के साथ वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी को स्थायी रूप से मजबूत करना होना चाहिए।

यह समय ऊर्जा आधारित विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के भी अनुकूल है। बेहतर अवसरचना, शिशाल घरेलू बाजार, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं और अपेक्षाकृत कम ऊर्जा लागत भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प बनाती हैं। यदि नीतिगत स्थिरता और सुधारों की गति बनी रहती है तो भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी भूमिका और मजबूत कर सकता है।

सनातन के अनुसार मनुष्य को गाय, भैंस या बकरी का दूध नहीं पीना चाहिये



पीना चाहिए या नहीं यह विषय वैज्ञानिक स्वास्थ्य तथा मानवीय पहलुओं पर निर्भर है, परंतु प्रत्येक जानवर का बच्चा अपनी मां का दूध पीता है इधर मनुष्य में बच्चा मां का दूध पीने के साथ जानवरों के दूध का सेवन करता है जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बीमारियों का घर है तथा जानवरों के बच्चों साथ अन्याय है, वैज्ञानिक रूप से जानवरों के दूध में वह सब तत्व मौजूद हैं जो जानवर को पुष्ट बनाते हैं, तथा जानवरों के गुण विकसित करते हैं, उसपर मानव का अधिकार नहीं है, डेरी प्रोडक्ट बंद करके देखें, बीमारियां गायब होने लगेंगी , शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी शुगर कम होगी नींद अच्छी आएगी , पशुओं का दूध मानव शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है, शरीर में इंफ्लुमेंट होगा यदि यह दूध बंद कर दिया जाए, ब्लड प्रेशर कम होगा, यह वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से गलत है,,, स्वास्थ्य हेतु,,1, गाय का दूध पचने में आसान होता है पर जल्दी पच जाता है इसके विपरीत भैंस का दूध भारी तथा गाढ़ा होता है इसे बचाने के लिए बेहतर पाचन शक्ति की आवश्यकता होती है, परंतु मनुष्य का नैतिक अधिकार नहीं है, जानवर के दूध पर, ,,,'किसी भी जानवर के दूध का सेवन करें क्योंकि है अधिकार जानवर के बच्चों का है यह जानवरों के बच्चों के अधिकारों का हनन है, आध्यात्मिक की दृष्टि से तथा वैज्ञानिक दृष्टि से भी ईंसान की जाह जानवरों के गुण विकसित होने लगते हैं, जानवरों का दूध सेवन करने से, जो आज संसार में अप्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, 2, लैक्टोज की समस्या, , विश्व की एक बड़ी आबादी लैक्टोज आ सहिष्णुता, (लैक्टोज इन्टोलरेंस) , से ग्रस्त है, जिसके कारण उन्हें दूध पीने से गैस या पेट की समस्या हो सकती है, कुछ विशेषज्ञों के अनुसार ईंसानी शरीर के लिए अन्य जीवों के दूध का सेवन प्राकृतिक रूप से उचित नहीं है, सावधानी तथा विकल्प,,1, कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है वह अच्छे शारीरिक श्रम करते हैं यह गाय का दूध का सेवन करते हैं दूध शरीर की पुष्टि करने और पूर्ति करने हेतु है, पर अंतर्मन, विचार, मस्तिष्क को ताकत नहीं दे सकते, इसके लिए पेड़ पौधे, बादाम का दूध, नारियल का दूध, ओट्स का उपयोग कर सकते हो, भैंस के दूध से ट्यूबर पथरी आदि रोग आते हैं, तथा भैंस के जीस आपके अंदर आने लगते हैं, साधारण मानव को नहीं पीना चाहिए यह प्रक्रिया अमेरिका जापान कोरिया में प्रतिबंधित है, वहां जानवर का दूध नहीं पिया जाता ।

अखिल विश्व सत्य सनातन संघ के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष उदित भटोरिया ने जानवरों के दूध पीने वालों पर कटाक्ष करते हुए बताया कि मनुष्य एकमात्र जीव है जो दूसरों का हक मारता है क्योंकि हर जानवर के दूध पर उसके बच्चे का अधिकार है जिस तरह मानव के अतिरिक्त कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता परंतु ईंसान अपनी मां के दूध के साथ-साथ जानवरों का दूध का सेवन भी करता है जो जानवरों के साथ आध्यात्मिक रूप से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अन्याय है, मानव को पशुओं का दूध पीना चाहिए या नहीं यह विषय वैज्ञानिक स्वास्थ्य तथा मानवीय पहलुओं पर निर्भर है, परंतु प्रत्येक जानवर का बच्चा अपनी मां का दूध पीता है इधर मनुष्य में बच्चा मां का दूध पीने के साथ जानवरों के दूध का सेवन करता है जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बीमारियों का घर है तथा जानवरों के बच्चों साथ अन्याय है, वैज्ञानिक रूप से जानवरों के दूध में वह सब तत्व मौजूद हैं जो जानवर को पुष्ट बनाते हैं, तथा जानवरों के गुण विकसित करते हैं, उसपर मानव का अधिकार नहीं है, डेरी प्रोडक्ट बंद करके देखें, बीमारियां गायब होने लगेंगी , शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी शुगर कम होगी नींद अच्छी आएगी , पशुओं का दूध मानव शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है, शरीर में इंफ्लुमेंट होगा यदि यह दूध बंद कर दिया जाए, ब्लड प्रेशर कम होगा, यह वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से गलत है,,, स्वास्थ्य हेतु,,1, गाय का दूध पचने में आसान होता है पर जल्दी पच जाता है इसके विपरीत भैंस का दूध भारी तथा गाढ़ा होता है इसे बचाने के लिए बेहतर पाचन शक्ति की आवश्यकता होती है, परंतु मनुष्य का नैतिक अधिकार नहीं है, जानवर के दूध पर, ,,,'किसी भी जानवर के दूध का सेवन करें क्योंकि है अधिकार जानवर के बच्चों का है यह जानवरों के बच्चों के अधिकारों का हनन है, आध्यात्मिक की दृष्टि से तथा वैज्ञानिक दृष्टि से भी ईंसान की जाह जानवरों के गुण विकसित होने लगते हैं, जानवरों का दूध सेवन करने से, जो आज संसार में अप्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, 2, लैक्टोज की समस्या, , विश्व की एक बड़ी आबादी लैक्टोज आ सहिष्णुता, (लैक्टोज इन्टोलरेंस) , से ग्रस्त है, जिसके कारण उन्हें दूध पीने से गैस या पेट की समस्या हो सकती है, कुछ विशेषज्ञों के अनुसार ईंसानी शरीर के लिए अन्य जीवों के दूध का सेवन प्राकृतिक रूप से उचित नहीं है, सावधानी तथा विकल्प,,1, कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है वह अच्छे शारीरिक श्रम करते हैं यह गाय का दूध का सेवन करते हैं दूध शरीर की पुष्टि करने और पूर्ति करने हेतु है, पर अंतर्मन, विचार, मस्तिष्क को ताकत नहीं दे सकते, इसके लिए पेड़ पौधे, बादाम का दूध, नारियल का दूध, ओट्स का उपयोग कर सकते हो, भैंस के दूध से ट्यूबर पथरी आदि रोग आते हैं, तथा भैंस के जीस आपके अंदर आने लगते हैं, साधारण मानव को नहीं पीना चाहिए यह प्रक्रिया अमेरिका जापान कोरिया में प्रतिबंधित है, वहां जानवर का दूध नहीं पिया जाता ।

योग दिवस पर ओजस योग मंदिर का योग महायज्ञ

रायगढ़ में एक साथ 7 जगहों पर 300 से अधिक लोगों ने किया योग, संचालिका श्रेया अग्रवाल ने कहा – योगमय जीवन के लिए समर्पित रहेगा जीवन

रायगढ़

पिछले दो दशकों से घर-घर योग पहुंचाने के लिए समर्पित ओजस योग मंदिर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रायगढ़ जिले में योग महायज्ञ का आयोजन किया। संस्था द्वारा एक ही दिन में 7 अलग-अलग स्थानों पर 300 से अधिक लोगों को योगाभ्यास कराया गया। संस्था की संचालिका श्रेया अग्रवाल ने कहा, योगमय जीवन बनाने के लिए मेरा जीवन समर्पित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से योग को 180 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वीकार किया। योग के जरिए भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में बड़ा कदम उठा चुका है। एनटीपीसी



लारा में योग प्रशिक्षिका भावना, आस्था व गायत्री ने 72 लोगों को योग कराया। विशिष्ट अतिथि श्रीमती रेखा ठाकुर (अध्यक्षा, PMS) ने कहा,

अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित योग आवश्यक है। सुभाष ठाकुर ने स्वस्थ जीवनशैली के लिए योग को जरूरी बताया। सभी ने नियमित योग का

संकल्प लिया। ओजस योग मंदिर केंद्र में कांता, सोनाली व सुमन ने योग कराया। ईशा अग्रवाल ने कहा, युवा पीढ़ी मोबाइल के अधिक उपयोग

से योग से दूर हो रही है। देर रात सोने-जागने से ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। जैसे रोज नहाना जरूरी है, वैसे ही बीमारी से बचने के लिए रोज योग जरूरी है। ऑनलाइन क्लासेज में श्रेया अग्रवाल ने 35 लोगों को ऑनलाइन योग कराया। पुष्पा शर्मा, यशोदा यादव व जीतू यादव ने केंद्र में प्रशिक्षण दिया। श्रेया ने कहा, आज पूरे विश्व में योग की चर्चा है, हर घर में योग जरूरी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में विद्या निषाद, नीलम यादव व रीना बंजारे ने 55 लोगों को योग कराया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय जितेंद्र कुमार जैन जी की प्रेरणादायक उपस्थिति रही। सभी ने नियमित योग का संकल्प लिया। हिंडालको इंडस्ट्रीज, बेलजोर

किंडकेल में अर्पणा, चांदनी व निकिता ने 55 लोगों को प्रशिक्षण दिया। गारे पेलमा IV/4 कोल माइंस के यूनिट हेड राजीव कुमार व एचआर हेड प्रेम कुमार सिंह मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने कहा, आज की जीवनशैली में तनाव मुक्ति और स्वास्थ्य के लिए योग जरूरी है। कोतरा रोड, प्रवीण बंसल के मार्गदर्शन में पायल व उमा ने 30 लोगों को सामूहिक योग कराया। प्रवीण बंसल ने कहा, नियमित योग से एकाग्रता आती है, यह जीवन के लिए सबसे आवश्यक है। ओजस योग मंदिर की संचालिका श्रेया अग्रवाल संजय अग्रवाल की सुपुत्री हैं। संस्था लगातार ऑनलाइन-ऑफलाइन माध्यम से योग को जन-जन तक पहुंचा रही है।

ओवर रेटिंग की शिकायतों के बाद आबकारी विभाग में फेरबदल

छत्तीसगढ़ में 30 अधिकारियों का ट्रांसफर



रायपुर

छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में लगातार सामने आ रही ओवर रेटिंग की शिकायतों के बाद आबकारी विभाग ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। विभाग ने प्रदेश के 30 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए हैं। इसमें कई जिला आबकारी अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं, जबकि कई अधिकारियों को नई जगहों पर स्वतंत्र जिम्मेदारी दी गई है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में शराब की तय कीमत से ज्यादा वसूली की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। विभाग की ओर से मैदानी अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए थे। कुछ मामलों में अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया था। इसके बाद अब विभाग ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव किया है। जारी आदेश के अनुसार, रायपुर जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार शर्मा को अब सहायक आयुक्त आबकारी राजनांदगांव की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रवीण वर्मा, सहायक आयुक्त आबकारी को प्रभारी उपायुक्त आबकारी जिला रायपुर बनाया गया है। इसी तरह रत्नेश मरावी को जिला आबकारी अधिकारी सक्ती (स्वतंत्र प्रभार), नितिन कुमार शुक्ल को जिला आबकारी अधिकारी मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी, सीआर साहू को जिला आबकारी अधिकारी खैरागढ़-छुईखदान-गंडई की जिम्मेदारी दी गई है।

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को यह समझना होगा कि राजस्व संग्रहण केवल विभागीय कार्य नहीं, बल्कि शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार का आधार है। यदि राजस्व संग्रहण बेहतर होगा तो नगर निगम अधिक प्रभावी ढंग से विकास कार्यों का संचालन कर सकेगा। राजस्व वसूली नगर निगम की जीवनरेखा है। इसलिए राजस्व शाखा के सभी अधिकारी और कर्मचारी को तय लक्ष्य प्राप्त के लिए अभी से करें सुनियोजित कार्य करना होगा। उक्त बातों आज नगर निगम आयुक्त श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय ने कहा कि राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में कही। इस दौरान उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व वसूली की प्रगति का आकलन किया। बैठक में सहायक राजस्व निरीक्षकों, कर संग्रहकों एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों से वार्डवार संपत्तिकर, समेकित कर, जलकर एवं यूजर चार्ज की वसूली की स्थिति की

राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में आयुक्त ने दिए शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश

राजस्व वसूली नगर निगम की जीवनरेखा, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अभी से करें सुनियोजित कार्य : आयुक्त क्षत्रिय

रायगढ़।



जानकारी ली गई। समीक्षा के दौरान आयुक्त श्री क्षत्रिय ने कहा कि गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त उपलब्धियों को आधार बनाते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी शत-प्रतिशत राजस्व लक्ष्य प्राप्ति के लिए अभी से सुनियोजित एवं व्यवस्थित रूप से कार्य प्रारंभ करना होगा। उन्होंने सभी सहायक राजस्व निरीक्षकों को प्रतिदिन, साप्ताहिक,

मासिक एवं त्रैमासिक प्रगति का प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, जिससे वसूली कार्यों की नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन किया जा सके। इस अवसर पर आयुक्त श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय ने कहा कि राजस्व विभाग नगर निगम का सबसे महत्वपूर्ण और अभिन्न विभाग है। नगर निगम की वित्तीय सुदृढ़ता का आधार राजस्व संग्रहण ही है। राजस्व से प्राप्त राशि के माध्यम से कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाता है तथा शहरवासियों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, अधोसंरचना विकास, स्वच्छता, पेयजल, सड़क,

प्रकाश व्यवस्था सहित विभिन्न जनहितकारी कार्यों का संचालन किया जाता है। बैठक में राजस्व वसूली की रणनीति, बकाया कर संग्रहण, वार्डवार प्रगति तथा आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बड़े बकायादारों को करें टारगेट आयुक्त श्री क्षत्रिय ने सभी सहायक राजस्व निरीक्षकों को अपने-अपने प्रभार क्षेत्र के बड़े बकायादारों की पृथक सूची तैयार करने तथा उनसे सतत संपर्क स्थापित कर लंबित कर राशि जमा कराने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने करदाताओं को कर भुगतान

के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ बड़े बकायादारों के विरुद्ध नियमानुसार नोटिस जारी करने, कुर्की वारंट की कार्यवाही करने तथा आवश्यकतानुसार सीलिंग की कार्यवाही में तेजी लाने की बात कही, ताकि राजस्व संग्रहण में अपेक्षित वृद्धि सुनिश्चित हो सके। कम वसूली पर नाराजगी, अच्छे कार्यों की सराहना बैठक में आयुक्त श्री क्षत्रिय ने उन सहायक राजस्व निरीक्षकों के प्रति नाराजगी व्यक्त की, जिनकी वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रगति अपेक्षाकृत कम रही है। उन्होंने ऐसे अधिकारियों को अपने कार्यों में सुधार लाते हुए वसूली अभियान को गति देने के निर्देश दिए, वहीं जिन सहायक राजस्व निरीक्षकों ने निर्धारित अर्वाधि में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपेक्षाकृत अधिक राजस्व संग्रह किया है, उनके कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया।

मुख्यमंत्री ने विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का किया शुभारंभ

रायपुर

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज यहां राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सोमनाथ मंदिर हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक गौरव और आस्था का प्रमुख केंद्र है। सोमनाथ मंदिर को अनेक बार आक्रांताओं ने तोड़ा, लेकिन हर बार मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, ये



देशवासियों की अटूट आस्था का परिणाम है। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के तहत विशेष ट्रेन से छत्तीसगढ़ से सोमनाथ के लिए 1000 से अधिक

पावन भूमि के माटी कलश और पावन नदियों का जल कलश बाबा सोमनाथ को अर्पण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने भगवान सोमनाथ से छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की प्रार्थना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरवशाली दिन है जब प्रदेश भर से 1000 से अधिक श्रद्धालु भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में 11 जनवरी 2026 से 11 जनवरी

2027 तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व राष्ट्रीय स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस पर्व के अंतर्गत सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, उन्होंने भारत की आजादी के बाद राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक के रूप में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। 75 वर्ष पूर्व देश के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद जी ने पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण किया था।

3 दिन में निगम ने वसूला 2.24 करोड़ का टैक्स



रायपुर। रायपुर नगर निगम ने 22 जून को 630 संपत्तियों से 1 करोड़ 21 लाख 33 हजार 177 रुपए की वसूली की। इससे पहले 19 जून को 525

संपत्तियों से 1 करोड़ 3 लाख 12 हजार 440 रुपए का राजस्व संग्रह किया गया था। यानी महज तीन दिन में निगम ने 2 करोड़ 24 लाख रुपए से अधिक की टैक्स वसूली की है। निगम आयुक्त संवित मिश्रा के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 22 जून को विभिन्न जनों में लक्ष्य आधारित वसूली की गई। सबसे अधिक 33.47 लाख रुपए का राजस्व जून-4 से प्राप्त हुआ। वहीं जून-10 ने 18.99 लाख रुपए, जून-2 ने 11.61 लाख रुपए, जून-5 ने 11.35 लाख रुपए और जून-7 ने 10.43 लाख रुपए की वसूली की। इससे पहले 19 जून को निगम राजस्व विभाग ने 525 संपत्तियों से 1 करोड़ 3 लाख 12 हजार 440 रुपए की वसूली कर एक दिन में एक करोड़ से ज्यादा कलेक्शन का आंकड़ा पार किया था। निगम प्रशासन का मानना है कि संपत्तिकर में मिल रही छूट के कारण बड़ी संख्या में करदाता समय से टैक्स जमा कर रहे हैं। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे 30 जून 2026 तक अपना संपत्तिकर जमा कर 6.25 प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ लें। निगम के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित संपत्तिकर की पूरी राशि समय सीमा के भीतर जमा करने वाले करदाताओं को यह छूट दी जा रही है।

प्रदेश का सबसे मॉडल शहर बनेगा रायगढ़- वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी

नगर निगम क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का वित्त मंत्री ने किया निरीक्षण

■मरीन ड्राइव से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड तक, विकास कार्यों की प्रगति का लिया जायजा
■आगामी नवंबर माह तक मरीन ड्राइव का निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देश
■रायगढ़ को मिलेगा अत्याधुनिक बस टर्मिनल, एक साथ 30 बसों के संचालन और 550 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था

रायगढ़

प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी ने सोमवार सुबह नगर निगम क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने शहर के बहुप्रतीक्षित मरीन ड्राइव, नए अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड (आईएसबीटी), एफसीआई ऑक्सीजन, मिट्टुमुड़ा तालाब, किसान राइस मिल ऑक्सीजन और कयाघाट पुल सहित अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का स्थल पर पहुंचकर अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को सभी



कार्यों में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्माण पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नगर निगम महापौर श्री जीवर्धन चौधान, कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी उपस्थित रहे। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए कहा कि रायगढ़ को प्रदेश के सबसे आधुनिक, व्यवस्थित और सुविधासंपन्न शहरों में शामिल करना उनका संकल्प है। उन्होंने कहा कि सड़क, परिवहन, पर्यावरण, जल संरक्षण और शहरी सुविधाओं से जुड़े इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद रायगढ़ विकास के नए

आयाम स्थापित करेगा और प्रदेश के लिए एक मॉडल शहर के रूप में उभरेगा। वित्त मंत्री ने प्रगति नगर स्थित निर्माणधीन मरीन ड्राइव का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने समय पर मुख्य बॉक्स क्लवर्ट और डायवर्सन निर्माण कार्य पूरा होने पर सतोष व्यक्त करते हुए संबंधित एजेंसियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मरीन ड्राइव केवल एक सड़क परियोजना नहीं बल्कि रायगढ़ की नई पहचान बनने जा रही है। इससे शहर का सौंदर्य बढ़ेगा, यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और नागरिकों को एक आकर्षक सार्वजनिक स्थल मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी नवंबर माह तक परियोजना को हर हाल में पूर्ण किया जाए ताकि शहरवासियों को जल्द इसका लाभ मिल सके।

प्लेसमेंट के नाम पर चेन्नई गई 3 युवतियां बनीं बंधक



सरगुजा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सीतापुर की 3 युवतियां प्लेसमेंट के नाम पर चेन्नई पहुंचने के बाद वहां फंस गई हैं। लड़कियों ने वीडियो जारी कर कहा कि, उन्हें घर लौटने नहीं दिया जा रहा है। वापस जाने के लिए 10-10 हजार रुपए जमा करने की शर्त रखी जा रही है। सीतापुर विधायक रामकुमार टोपों ने कहा कि, आज 12.30 बजे लड़कियों को वहां से निकाल लिया गया है। बहुत जल्द वो छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगी। उन्होंने अपील की है कि, कभी भी बाहर जाएं, तो किसी न किसी नंबर जरूर रखें। जिससे मदद मांगी जा सके। जानकारी के अनुसार, सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम भरतपुर बेलजोरा की प्रतिमा, राधा और जगेश्वरी ने जशपुर में 3 महीने का सिलार्ड की ट्रेनिंग ली थी। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बताया गया था कि, चेन्नई में प्लेसमेंट मिलेगा और यदि वहां काम पसंद नहीं आए तो वे वापस घर लौट सकती हैं। इसी भरोसे पर तीनों युवतियां चेन्नई जाने के लिए तैयार हुई थीं। युवतियों ने वीडियो में बताया कि, उन्हें दो युवती और एक युवक चेन्नई ले गए थे। अब जिस जगह उन्हें काम पर रखा गया है, वहां से वापस लौटने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें चेन्नई छोड़ने वाले लोग अब फोन भी नहीं उठा रहे हैं। युवतियों का कहना है कि, जब उन्होंने घर लौटने की इच्छा जताई तो पहले कुछ नहीं दिया जा रहा। तीनों युवतियों ने वीडियो के माध्यम से प्रशासन और परिजनों से मदद की अपील की है। उनका कहना है कि वे सुरक्षित अपने घर लौटना चाहती हैं, लेकिन उन्हें वहां से निकलने नहीं दिया जा रहा। युवतियों का वीडियो परिजनों के माध्यम से सीतापुर विधायक रामकुमार टोपों को मिला तो उन्होंने सरगुजा एसपी राजेश अग्रवाल से बात की। विधायक ने तीनों युवतियों की सकुशल वापसी के लिए पहल करने कहा। प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से तीनों युवतियों को छुड़ा लिया गया है। सीतापुर विधायक ने तीनों युवतियों से वीडियो काल पर बात भी की। विधायक ने ट्रेन को लेकर पूछा तो युवतियों ने बताया कि शाम पाँच बजे वहां उनकी ट्रेन है। विधायक ने कहा कि उन्हें पैसे भी भेजे जा रहे हैं। रास्ते में संपर्क में रहें और जरूरत पड़ने पर काल कर लें।

स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर विभिन्न स्थानों पर किया गया योग

रायगढ़

जिंदल पॉवर तमनार द्वारा योग दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर योग अभ्यास का आयोजन किया गया। इन स्थानों पर योग शिक्षकों द्वारा विभिन्न प्रकार के आसन कराए गए। योग गुरुओं द्वारा लोगों को योग का महत्व बताया गया साथ ही योग को नियमित रूप से करने के लिए प्रेरित भी किया गया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को देश भर में 12वां योग दिवस मनाया गया। इस वर्ष स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर योगाभ्यास कराया गया। जिंदल पावर तमनार द्वारा भी प्लांट एरिया के गांवों तमनार, कुंजेपुरा, सलहारी और बरकस पाली में सुबह योगाभ्यास का आयोजन किया गया। इन स्थानों पर बड़ी संख्या में ग्रामीण व विद्यार्थियों ने योगाभ्यास किया। तमनार में योग प्रशिक्षिका रुक्मणी पटनायक ने योगाभ्यास कराया। इसी प्रकार जिंदल चिल्ड्रन होम गर्ल्स एवं बॉयज में



अलग अलग योगाभ्यास कराया गया। ओपी जिंदल स्कूल राबो में भी योग दिवस पर योगाभ्यास कराया गया। यहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। माईंस एरिया के हाईस्कूल समकेरा, प्राइमरी स्कूल नागरामुड़ा, हाई स्कूल लिबरा, मिडिल स्कूल सारसमाल, और पासकीय हाईस्कूल कोलम (चितवाही) में योगाभ्यास का

आयोजन कराया गया। ओपी जिंदल स्कूल के ऑडिटोरियम में भी योग आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में जिंदल पॉवर के अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिजन शामिल हुए। यहां एक्सपर्ट योग गुरु द्वारा लोगों को अनुलोम, विलोम, कपालाभाति, पवासन आदि आसनों का अभ्यास कराया गया।

न्यूज़ ब्रीफ

बरेली सेंट्रल जेल से उग्रकैद का कैदी भागा:खेती का काम करने फॉर्म पर गवा था; 4 टीमें ढूँढ रहीं



बरेली, बरेली सेंट्रल जेल में उग्रकैद की सजा काट रहा एक बंदी सोमवार को फरार हो गया। घटना सामने आते ही डीजी जेल पीसी मीणा ने 7 अफसरों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक अविनाश गौतम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए रिपोर्ट शासन को भेजी है।

डीजी जेल ने बताया- सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे जेल के बाहर कृषि फार्म कमान नंबर-1 से एक बंदी के गायब होने की सूचना मिली। इसके तुरंत बाद जेल परिसर में अलार्म बजाया गया। अफसरों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।

प्रारंभिक जांच में पता चला कि कृषि कार्य के लिए भेजा गया बंदी दिनेश कुमार भाग गया है। वह अमरोहा के नन्हेड़ा गांव का रहने वाला है। इसके बाद जेल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया। बंदी दिनेश को अमरोहा की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 9 जनवरी, 2026 को दोषी ठहराते हुए उग्रकैद और जुमाने की सजा सुनाई थी। उसे 19 अप्रैल, 2026 को बिजनौर के जिला कारागार से स्थानांतरित कर बरेली केन्द्रीय कारागार भेजा गया था। जेल रिकॉर्ड के अनुसार, सोमवार सुबह 7:22 बजे दिनेश कुमार को 45 अन्य बंदियों के साथ कृषि कार्य के लिए बाहरी फार्म पर भेजा गया था।

जयपुर में महिला पर फेंका तेजाब:आरोपी युवक घर से भगाकर लेकर आया था, पत्नी-बच्चों के आने पर छोड़कर भागा



जयपुर, जयपुर में एक पार्क के अंदर महिला पर तेजाब फेंकने (एसिड अटैक) का मामला सामने आया है। महिला का बॉयफ्रेंड उसे घर से भगाकर जयपुर लेकर आया था। इस बीच उसे छोड़कर अपनी पत्नी और बच्चों के पास चला गया। इसके बाद मिलने के बहाने बुलाकर तेजाब फेंककर भाग गया।

पुलिस ने पीड़िता का जयपुरिया हॉस्पिटल में इलाज करवाया। उसकी रिपोर्ट पर सोमवार शाम मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार- जयपुर में रह रही पीड़िता (37) ने रिपोर्ट दर्ज करवाकर बताया कि कुछ समय पहले आरोपी युवक से उसकी मुलाकात हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी ने उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। शादी करने का झूठा वादा कर करीब 3 महीने पहले अपने साथ जयपुर लेकर आ गया।

जयपुर लाने के बाद किराए के मकान में रखा। पीड़िता का आरोप है कि पत्नी-बच्चों के आने पर वह उसे छोड़कर उनके पास रहने चला गया। उसके मोबाइल पर कॉल किया तो गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देने लगा। इस बीच 20 जून को आरोपी बॉयफ्रेंड ने सुबह करीब 11:30 बजे पार्क में मिलने बुलाया। पार्क में एक बैग लेकर मिलने आया। वहां धमकाकर बैग से तेजाब की बोतल निकालकर उसकी पीट पर फेंक दिया।

UAE, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकता है:एयर डिफेंस सिस्टम आकाशतीर पर भी बातचीत जारी

नई दिल्ली, भारत और UAE के बीच रक्षा क्षेत्र में नई बातचीत शुरू हुई है। रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, UAE ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर कहर बरपाने वाली भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और आकाशतीर एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। इस संबंध में दोनों देशों के बीच शुरुआती चर्चा चल रही है।

ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में शामिल है। इसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया किया है। यह मिसाइल जमीन, समुद्र और फाइटर जेट से दागी जा सकती है। हालांकि यह भारत-रूस का जॉइंट प्रोजेक्ट है, इसलिए इसके निर्यात के लिए रूस की मंजूरी जरूरी होती है। सूत्रों का कहना है कि मॉस्को और अबू धाबी के बीच करीबी संबंधों को देखते हुए इसके रास्ते में कोई रुकावट आने की संभावना नहीं है।



हाल के महीनों में ईरान-इजराइल जंग और मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ी हैं। इसी वजह से श्व अपनी सैन्य ताकत मजबूत कर रहा है।

तेल और व्यापार के लिए अहम होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी, शिप, एयरक्राफ्ट या जमीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल का

TMC ने ममता को पार्टी प्रमुख बताया:EC को वर्किंग कमेटी की लिस्ट भेजी; बागी गुट ने अरूप रॉय को अध्यक्ष चुना था

कोलकाता, तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने चुनाव आयोग को पार्टी के पदाधिकारियों और नेशनल वर्किंग कमेटी की नई लिस्ट भेजी है। इसमें ममता बनर्जी को पार्टी का अध्यक्ष बताया गया है। सुभ्रत बक्शी को उपाध्यक्ष और अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव बताया है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग को भेजी गई लिस्ट 20 जून 2026 तक की संगठनात्मक स्थिति के आधार पर तैयार की गई है। इससे एक दिन पहले TMC के बागी गुट के नेता ऋतुब्रत बनर्जी ने TMC की पैरलल वर्किंग कमेटी का ऐलान किया था। विधायक अरूप रॉय अध्यक्ष चुना था।

इधर, TMC ने बागी गुट में शामिल होने वाले 8 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। TMC की लिस्ट के मुताबिक, डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन संयुक्त सचिव हैं। नेशनल वर्किंग कमेटी में कुल 24 नेताओं को नाम है। इसमें चंद्रिमा भट्टाचार्य, अमित मित्रा, राजेश पति त्रिपाठी, असीमा पात्रा, मलय घटक, गौतम देव, शोभनदेव चट्टोपाध्याय, बुलु चिक



बराइक, मुकुल संगमा, बैस्वानोर चट्टोपाध्याय, बीरबाहा हांसदा, कल्याण बनर्जी, सौगत रॉय, नदीमुल हक, मदन मित्रा, बिमान बनर्जी, महुआ मोइत्रा और कुणाल घोष को भी रखा गया है। सोमवार को विपक्ष के नेता ऋतुब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने कोलकाता में विशेष बैठक कर TMC की पैरलल नेशनल वर्किंग कमेटी बनाने का ऐलान किया था। गुट ने विधायक अरूप रॉय

को चेयरमैन चुना था। फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास, रंथन घोष और सबीना यास्मीन को वाइस चेयरमैन बनाया गया था। बागी नेताओं का कहना है कि फरवरी 2022 में बनी नेशनल वर्किंग कमेटी का कार्यकाल फरवरी 2026 में खत्म हो गया था। नई कमेटी नहीं बनने के कारण उन्होंने नया संगठनात्मक ढांचा तैयार किया। TMC नेता कुणाल घोष ने बागी गुट पर पार्टी के नाम का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वहीं, झुस्स सांसद सौगत रॉय ने भी बागी गुट को महत्व देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने पार्टी बनाई है और वही इसकी सबसे बड़ी पहचान है।

पंजाब- सगे भाइयों की 3 हजार करोड़ ठगी की कहानी: 27 फर्जी कंपनियां, सरकार को भी चूना

लुधियाना, पैसे-नौकरी के लालच में जरूरतमंदों के डॉक्यूमेंट्स लिए, उनसे 27 फर्जी कंपनियां खोलीं और 25 बैंक अकाउंट से 3089 करोड़ रुपए निकाल लिए, ठगी करने वाले ये 2 शातिर भाई पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ के हैं। जिन्होंने सरकार को भी 108.49 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट का चूना लगा दिया।

पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब इंफोसमेंट डायरेक्टोरेट(ED) और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंटेलिजेंस (DGGI) ने खुफिया जानकारी के तहत दोनों भाइयों अमित कुमार गोयल व मनीष कुमार का रिकॉर्ड खंगाला। जिसमें पता चला कि इन्होंने मंडी गोबिंदगढ़ के ही एक अन्य कारोबारी गौरव अग्रवाल के साथ मिलकर एक ग्राम माल की डिलीवरी तक नहीं की और कागजों पर हजारों करोड़ का टर्नओवर खड़ा कर दिया। ज्यादातर सबूत उनके मोबाइल से मिले। ED ने अब इस मामले में दोनों भाइयों समेत कुल पांच लोगों पर बाइनेम और बाकी अज्ञात लोगों पर लुधियाना के थाना जमालपुर में FIR दर्ज करवाई है। सगे भाइयों ने कैसे की ठगी, इसका पूरा खुलासा कैसे हुआ



और अब तक क्या कार्रवाई हुईजरूरतमंदों के KYC दस्तावेजों का दुरुपयोग ED ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि दोनों भाई किस तरीके से फर्जी कंपनियां बना रहे थे। इन्होंने बताया कि अमित गोयल और मनीष कुमार ने आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब लोगों को निशाना बनाया। मामूली पैसें का लालच देकर या नौकरी लगाने के नाम पर उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज (KYC) हासिल कर लिए। अमित गोयल ने केवल दो कंपनियां अपने पैन पर बनाई, जबकि बाकी की 25 कंपनियां इन

लोगों के नाम पर दर्ज करा दी गईं। 720 करोड़ के फर्जी बिल जारी कागजों पर खड़ी की गई इन 27 शेल कंपनियों के जरिए देश की कई अन्य बड़ी लाभार्थी कंपनियों को फर्जी इन्वॉइस यानि बिना माल की डिलीवरी के सिर्फ बिल जारी किए गए। इन बिलों की कुल कीमत 720.97 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की चोरी: शिकायत के अनुसार बिना माल खरीदे जो फर्जी बिल लाभार्थी कंपनियों को दिए गए थे, उनके आधार पर उन कंपनियों ने सरकार से 108.49 करोड़ रुपए का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)

'शादी के नाम पर बहलाया, 10 हजार का दिया लालच':मोतिहारी में छूमन ट्रैफिकिंग मामले में 5 अरेस्ट

मोतिहारी, "पहले मुझे शादी का झांसा दिया गया। मैंने साफ मना कर दिया तो उन लोगों ने पैसे का लालच देना शुरू कर दिया। जब मैं इसके लिए भी तैयार नहीं हुई तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया। मुझे शक है कि पानी में कुछ नशीला पदार्थ मिलाया गया था। पानी पीने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक होटल के कमरे में थी।



लेकिन वे लोग लगातार दबाव बना रहे थे। समय पर पुलिस नहीं पहुंचती तो पता नहीं मुझे कहाँ ले जाते।" ये कहना है पूर्वी चंपारण के मोतिहारी की रहने वाली संजू देवी का, जिसका पुलिस ने मानव तस्करी के चंगुल से रेस्क्यू किया है।

पिंपरा कोठी थाना क्षेत्र में पुलिस ने राजस्थान से जुड़े एक गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें तीन महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं। इस पूरे मामले में सबसे अहम है पुलिस संजू देवी की आपबीती। जिसने

पुलिस को बताया कि किस तरह उसे धीरे-धीरे बातों में उलझाकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश की गई।

संजू देवी ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा, मैं आरोपियों को पहले से नहीं जानती थी। मेरा उनलोगों से कोई संपर्क नहीं था। रविवार(21 जून) को मेरी बेटी की तबियत खराब थी। इसी वजह से शाम में उसके लिए दवा लेने निकली थी।

इसी दौरान छत्तीनौ मंदिर के पास मैं गई थी। वहीं ये लोग मिले। पहली बार ही उनसे मुलाकात हुई थी। वो लोग मेरे से बात करने लगे। मुझे अपने साथ चलने के लिए कहने लगे। उन्होंने कहा कि चलो हमारे साथ। मैंने कहा कि मैं नहीं जा सकती हूं। मेरा घर है, बच्चे हैं। मैं ऐसे किसी के साथ नहीं जा सकती।

बेंगलुरु में ट्रिपल मर्डर, माता-पिता और बेटी की हत्या:बड़ी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड फरार; दोनों से मिलने फ्लैट में पहुंचा था परिवार

बेंगलुरु, बेंगलुरु के केआर पुरम इलाके में एक अपार्टमेंट में एक ही परिवार के तीन लोगों का चाकू मारकर हत्या कर दी गई।

मृतकों की पहचान 52 साल के सोमसुंदर, उनकी पत्नी 48 साल की मुथुलक्ष्मी और 19 साल की बेटी सुप्रिया के रूप में हुई है।

माता-पिता और छोटी बेटी सोमवार शाम उस फ्लैट पर पहुंचे थे, जहां परिवार की बड़ी बेटी श्वेता और उसका बॉयफ्रेंड केनेथ रहते थे। वहीं पर तीनों के खून से लथपथ शव बरामद हुए। पुलिस को शक है कि बड़ी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस के मुताबिक, बड़ी बेटी श्वेता पिछले दो महीने से अपने बॉयफ्रेंड के साथ अलग फ्लैट में रह रही थी। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव चल रहा था।

परिवार बेटी से मिलने फ्लैट पहुंचा। मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ। पुलिस का मानना है कि इसी दौरान



दोनों आरोपियों ने तीनों पर कई बार चाकू से हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। है। आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की हैं।

कॉलेज छात्रों ने PG मालिक की बैट से पीटकर हत्या की

इधर बेंगलुरु में PG (पेइंग गेस्ट) मालिक की बैट से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में दो कॉलेज छात्रों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान 37 साल के माधव माटले के रूप में हुई है। घटना सोमवार शाम करीब 6:30 बजे कस्तूरीनगर मेन

रोड स्थित उनके PG के बाहर हुई। प्रारंभिक जांच के मुताबिक, राकेश और डॉन ब्राइट सन नाम के दो युवक PG कैंपस में लगे नल के पानी से अपने पैर धो रहे थे। PG मालिक ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी उस PG में नहीं रहते थे और घटना के समय शराब के नशे में थे। पुलिस के दौरान माधव माटले एक बैट लेकर आए। आरोप है कि दोनों युवकों ने बैट छीन लिया और उसी से उन पर हमला कर दिया।

गंभीर रूप से घायल माटले की बाद में मौत हो गई। राममूर्ति नगर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में राकेश BCom फाइनल ईयर का छात्र और डॉन ब्राइट सन BBA फर्स्ट ईयर का छात्र है।

भरत एनकाउंटर पर अनिरुद्धाचार्य बोले-सरकार को जनता पापी कहेगी:शरण में आए व्यक्ति को मारना पाप है

पटना, 17 जून को भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर पुलिस के रवैये पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी भरत एनकाउंटर पर बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, "जनता की हत्या करना किसी भी राजा के लिए पाप है। इस हाल में जनता आपको पापी राजा कहेगी। भरत ने किसी की हत्या नहीं की थी, अगर की होती तो एनकाउंटर कीजिए। गौ और ब्राह्मण हत्या से बचना चाहिए। किसी भी हत्या से बचना चाहिए। हर साल उसका गांव बाढ़ में डूब जाता था। वह अपने गांव की रक्षा के लिए नेताओं-अफसर से मित्रत्व कर रहा था।

अनिरुद्धाचार्य ने कहा- नेताओं का समझना चाहिए कि वे जनता से वोट लेते हैं। अगर वोट लेने के बाद उसी जनता को दबाना और मारना शुरू कर देंगे, तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सरकार ये ठीक नहीं कर रही।

अनिरुद्धाचार्य ने आगे कहा, "उस युवक ने किसी की हत्या करने या अपराध करने के मकसद से हथियार नहीं उठाया था। वह अपने इलाके और समाज



का काम करवाने के लिए अधिकारियों के पास गया था, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। ऐसे में उसने विरोध का रास्ता अपनाया। इसके बावजूद पुलिस ने उसे मार डाला। जब हम में से किसी की बात नहीं सुनी जाएगी तो कोई न कोई व्यक्ति आगे आएगा ही।" कथावाचक ने कहा, "यदि कोई व्यक्ति आतंकवादी है या उसने कई हत्याएं की हैं, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। अगर कोई आतंकवादी है, बड़ा अपराधी है, उसने 10-20 हत्याएं की हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए।" उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को गौ हत्या और ब्राह्मण हत्या से बचना चाहिए। इधर, सोमवार को ADG (लॉ एंड ऑर्डर) सुभांशु

कुमार ने कहा कि भरत तिवारी का जो मुठभेड़ मामले में दो FIR दर्ज की गई है। गोली चलाने का निर्देश किसने दिया, इन सारी बातों का जिक्र FIR में है। उन्होंने कहा कि इस मामले में लापरवाही सामने आई है कि जब पहली बार यानी 16 जून को पुलिस पदाधिकारी भरत तिवारी के घर गए, उसे पुलिस पदाधिकारियों ने ठीक से हेंडल नहीं किया, टाइमली उसे काबू में नहीं ला सके। 16 जून भोजपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें शाहपुर के रहने वाले 30 साल के भरत भूषण तिवारी ने पुलिस-प्रशासन को खुलेआम चुनौती दी और मांगों को पूरा न करने के संबंध में आरोप लगाए। दरअसल, शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के रहने वाले लोगों ने बताया कि पिछले 2 साल से शाहपुर प्रखंड के जवईनियां गांव और आसपास के लोग गंगा में आई बाढ़ के बाद कटाव से प्रभावित थे। पिछले साल यानी 2025 में जवईनियां गांव के 600 से ज्यादा घर गंगा में समा गए थे। तब से भरत पीड़ितों की आवाज उठा रहा था।

न्यूज़ ब्रीफ

गरीबी झेली, दर-दर भटके, अब बने 'एथलीट ऑफ द सेंचुरी' पिता ने छोड़ा, रंग पर झेले ताने



न्यूयॉर्क, दुनिया के महानतम बॉस्केटबॉल खिलाड़ियों में शुमार लेब्रॉन जेम्स आज करिअर के शिखर पर हैं, लेकिन उनका जीवन बड़े अभावों से भरा रहा है। हाल ही टाइम मैगजीन ने उन्हें कवर पेज पर स्थान देकर "एथलीट ऑफ सेंचुरी" बताया है।

"किंग जेम्स' के नाम से मशहूर लेब्रॉन को जीवन के संघर्ष जन्म से ही मिले। अमेरिका के एक्रोन शहर में 30 दिसंबर 1984 को जन्मे लेब्रॉन की मां ग्लोरिया जेम्स महज 16 साल की सिंगल मदर थीं। लेब्रॉन के जन्म से पहले ही उनके पिता परिवार छोड़ कर चले गए थे। ऐसे में उन्हें कभी भी पिता का प्यार नसीब नहीं हुआ। लेब्रॉन अपनी मां के साथ नानी के घर रहते थे। मां के पास आय का कोई साधन नहीं होने के कारण उनका बचपन अत्यंत गरीबी के हालात में गुजरा।

संघर्ष - परवरिश के लिए मां ने दूसरों को सौंपा, नस्लभेद का शिकार भी बने

जेम्स 5 साल के थे तो प्रशासन ने उनकी नानी का घर जर्जर बता कर गिरा दिया। मां-बेटे के पास कोई ठिकाना नहीं था। वे रिश्तेदारों, दोस्तों के घरों में रहते थे। 5 से 9 साल की उम्र में जेम्स और उनकी मां को एक दर्जन मकान बदलने पड़े।

जेम्स ने एक साक्षात्कार में बताया कि चौथी कक्षा में वे सी दिन तक स्कूल नहीं जा पाए। बेटे की परवरिश लायक पैसे नहीं थे तो मजबूरन मां ने नौ साल के जेम्स को अपने परिचित फुटबॉल कोच फ्रैंकी वॉकर को सौंप दिया।

उन्हें कई वर्ष मां से दूर रहकर बिताने पड़े। करिअर में जेम्स को नस्लभेद भी झेलना पड़ा। मैदान में उनके रंग पर टिप्पणी की जाती थीं।

2017 में उनके घर की दीवारों पर नस्लभेदी शब्द लिखे गए। जेम्स ने सार्वजनिक बयान में कहा, आप भले ही कितने ही मशहूर हों, लेकिन अमेरिका में अश्वेत होना मुश्किल भरा है।

शुरुआत - हाई स्कूल टूर्नामेंटों से बनी पहचान, एनबीए टीम का अनुबंध मिला

कोच वॉकर ने जेम्स की कद-काठी देख कर उन्हें बॉस्केटबॉल से परिचित कराया। जल्द ही जेम्स स्कूल टीम से खेलने लगे। हाई स्कूल टूर्नामेंटों में उनका प्रदर्शन इतना दमदार रहा कि उन्हें तीन बार ओहायो मिस्टर बॉस्केटबॉल चुना गया। उनकी ख्याति और प्रदर्शन देख कर 2003 में क्लीवलैंड कैवेलियर्स टीम ने उनसे एनबीए के लिए पहला अनुबंध किया।

सफलता - ओलंपिक और एनबीए खिताब जीते, गरीब बच्चों को देते हैं फ्री शिक्षा

जेम्स तीन बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे हैं। चार एनबीए चैंपियनशिप जीत कर वे ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर बने हैं।

जेम्स की सामाजिक संस्था आई प्रॉमिस स्कूल के जरिए गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा और कॉलेज स्कॉलरशिप देती है। उनकी खुद की फिल्म निर्माण कंपनी है, जबकि कई स्पोर्ट्स ब्रांड के साथ उनके अनुबंध हैं। उनकी नेटवर्थ 1.4 बिलियन डॉलर बताई जाती है।

भज्जी ने माना- श्रीसंत को थप्पड़ जड़ना बड़ी गलती थी:बोले- 5 सेकेंड के गुस्से ने इमेज खराब की; श्रीसंत बॉक्सिंग रिंग की चुनौती दे चुके

जालंधर, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के सबसे चर्चित विवादों में से एक 'स्लैपगेट' फिर सुर्खियों में है। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह उर्फ भज्जी ने उस पुराने विवाद पर अफसोस जताते हुए इसे अपने जीवन के सबसे खराब फैसलों में से एक करार दिया है।

21 जून को एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुए पांडेकास्ट में हरभजन सिंह ने इस पूरे विवाद पर गहरा दुख व्यक्त किया। भज्जी का मानना है कि मैदान पर जो कुछ भी हुआ, वह नहीं होना चाहिए था। अगर उधर अतीत की किसी एक गलती को सुधारने का मौका मिले, तो वह इसी घटना को चुनेंगे।

हरभजन ने कहा- वह केवल 5 सेकेंड का गुस्सा था। उस जरा से गुस्से ने इतनी सारी परेशानी, नेगेटिव एनर्जी और टकराव पैदा कर दिया। उस एक



पल की वजह से मेरी इमेज बहुत खराब हुई। जब भी मैं उस बारे में सोचता हूं, मुझे लगता है कि वह एक बहुत ही बुरा फैसला था। इससे पहले पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज एस. श्रीसंत ने दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह उर्फ भज्जी को खुलेआम

बॉक्सिंग रिंग में मुकाबले की चुनौती दी। श्रीसंत हाल ही में जारी एक विज्ञापन से मुझे लगता है कि वह एक बहुत ही बुरा फैसला था। इससे पहले पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज एस. श्रीसंत ने दिग्गज स्पिनर एस श्रीसंत का गुस्सा फूट पड़ा। 18 जून

वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया की 3 नंबर जर्सी मिली:कहा- खुशी बयां करने के लिए शब्द नहीं, आयरलैंड-इंग्लैंड दौरे पर रवाना

वैभव सूर्यवंशी सीनियर टीम इंडिया के साथ आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर मंगलवार को रवाना हो गए।

BCCI की ओर से उन्हें 3 नंबर जर्सी होटल भिजवाई गई, जिसे सूर्यवंशी काफी देर तक देखते रहे। सूर्यवंशी को जर्सी भारतीय टीम में थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट रघु ने सौंपी। सूर्यवंशी ने सबसे पहले रघु के पैर छूए और उन्हें प्रणाम किया, फिर जर्सी ली। इस पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड भी किया गया।

सूर्यवंशी बोले- आज वह सपना पूरा हो गया

इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जिस दिन पहली बार बल्लू थामकर मैदान पर कदम रखा था, आज वह सपना पूरा हो गया है। यह मेरे अब तक के करियर का सबसे बड़ा कदम है और इस अहसास को शब्दों में बयां करना

नामुमकिन है।

15 साल के सूर्यवंशी को पहली बार भारतीय टीम में जगह दी गई है।

देश की नेशनल टीम में सिलेक्ट होने वाले वे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। भारतीय टीम का आयरलैंड दौरा 26 जून से शुरू हो रहा है और इंग्लैंड दौरा 1 जुलाई से शुरू होगा।

सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद

आयरलैंड के बेलफास्ट में 26 या 28 जून को होने वाले मैच



मेसी के फुटबॉल वर्ल्डकप में सबसे ज्यादा 18 गोल:जर्मनी के वलोजा का रिकॉर्ड तोड़ा; अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया

अर्जेंटीना के कप्तान

लियोनेल मेसी फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ऑस्ट्रिया के खिलाफ मेसी ने पहले अपना 17वां गोल दागकर जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजा (16 गोल) का रिकॉर्ड तोड़ा और फिर मैच के आखिरी में एक

और गोल कर इसे 18 तक पहुंचा दिया। मेसी ने डलास स्टेडियम में 39वें मिनट में फोल्ड गोल लगाकर इतिहास रचा। इसके बाद इंजरी टाइम (95वें मिनट) में उन्होंने दूसरा गोल दागकर अर्जेंटीना की 2-0 की जीत पक्की कर दी। इस जीत के साथ मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ-32 में भी जगह बना



ली। 38 साल के मेसी ने पिछले मैच में अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी। मौजूदा टूर्नामेंट में उनके सबसे ज्यादा 5 गोल हो गए हैं। मेसी के बाद 3 गोल के साथ जर्मनी के डेनिज उंडाव हैं। मेसी के पास नौवें मिनट में ही रिकॉर्ड बनाने का मौका था। लॉटारो मार्टिनेज पर ऑस्ट्रियाई डिफेंडरों के फाउल

के बाद अर्जेंटीना को पेनल्टी मिली, लेकिन मेसी शॉट को पोस्ट के बाहर मार बैठे। इसके साथ ही वह वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा तीन पेनल्टी मिस करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए। इससे पहले घाना के असामोआ ग्यान ने दो पेनल्टी मिस की थीं। पेनल्टी चूकने के बाद 18वें मिनट में मेसी को एक

संजू बोले- धोनी क्रिकेट के फेडरर, कोहली अल्काराज जैसे:महिला टीम का वर्ल्डकप जीतना इंसपयरिंग था

विंबलडन से पहले भारतीय विकेटकीपर संजू सैमसन ने क्रिकेट और टेनिस के प्लेयर्स के बीच तुलना की। उन्होंने जियोस्टार से बातचीत में कहा कि अगर क्रिकेट में किसी खिलाड़ी की तुलना रोजर फेडरर से की जा सकती है तो वह पूर्व भारतीय कप्तान एम एस धोनी हैं। वहीं उन्होंने विराट कोहली की तुलना टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज से की।

सैमसन ने 2025 में भारत की महिला टीम के वनडे वर्ल्ड कप खिताब को भी याद किया। उन्होंने कहा कि पूरा देश फाइनल देख रहा था और उस जीत ने भारतीय क्रिकेट को नई दिशा दी।

सैमसन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने को लेकर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा, जब हम बड़े हो रहे थे तब लगभग हर वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ही जीतता था। यही वजह है कि उनके लिए हमारे मन में काफी सम्मान है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं।



विराट कोहली

हम चैंपियन हैं और उसी सोच के साथ मुकाबला करते हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सम्मान तो है, लेकिन डर नहीं।

सैमसन ने कहा, क्रिकेट के रोजर फेडरर एमएस धोनी हैं। वह जिस तरह अपने काम को अंजाम देते हैं। उसमें गजब का धैर्य और शांति दिखती है। जब वह अच्छा खेलते हैं तो सब कुछ बेहद आसान नजर आता है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। दूसरी ओर कार्लोस अल्काराज काफी अटैकिंग

प्लेयर हैं। विराट भाई ने भी अपने करियर की शुरुआत उसी अंदाज में की थी। वे एनर्जी से भरे रहते हैं, इसलिए उनकी तुलना अल्काराज से की जा सकती है। सैमसन ने 2025 में भारत की वर्ल्ड कप जीत पर कहा, हम सभी फाइनल देख रहे थे। मेरा परिवार और देशभर के लोग टीवी के सामने बैठे थे। यह पूरे देश के लिए बेहद खास पल था। हमें हमेशा विश्वास था कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, लेकिन मंजिल अभी भी दूर लगती थी।

27 करोड़ के पंत 15 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स लौटे:13.50 करोड़ में कुलदीप लखनऊ में शामिल, दोनों टीमों के बीच ट्रेड हुआ

IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स (DC) में वापसी हो गई है, जबकि स्पिनर कुलदीप यादव अब लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए खेलेंगे। दोनों टीमों के बीच यह ट्रेड हुआ है। इस IPL के बाद पंत ने लखनऊ की कप्तानी छोड़ दी थी।

लखनऊ ने IPL 2025 के ऑक्शन में पंत को रिकॉर्ड 27 करोड़ रुपए में खरीदा था, जो IPL इतिहास की सबसे बड़ी बोली थी। अब ट्रेड के बाद वे 15 करोड़ रुपए की फीस पर दिल्ली से जुड़े हैं। वहीं, कुलदीप यादव 13.50 करोड़ रुपए की अपनी मौजूदा फीस पर लखनऊ में शामिल हुए।

पंत एक बार फिर उसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा बन गए हैं, जहां उन्होंने साल 2016 से 2024 के बीच अपने करियर के 9 सीजन बिताए थे। दिल्ली कैपिटल्स के लिए पंत ने अब तक कुल 111 मैच खेले हैं।

उन्होंने तीन सीजन में 43



अक्षिता राज के साथ विवाह बंधन में बंधेंगे। शादी समारोह के लिए वाराणसी के होटल ताज गंगेज को बुक किया गया है। इस पूरे फंक्शन में सिर्फ परिवार लोग शामिल होंगे। इससे मीडिया को दूर रखा गया है। शादी समारोह में क्रिकेट जगत की कई हस्तियों के शामिल भी हो सकते हैं।

आकाश दीप के घर पर शादी

से पहले हुई मेहंदी सेरेमनी में घर का माहौल पूरी तरह जश्न में बदल गया।

परिवार के लोगों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में आकाश दीप की मेहंदी रस्म धूमधाम से पूरी की गई। परंपरिक गीतों की गुंज, ढोलक की थाप और अपनों की हंसी-खुशी के बीच पूरे परिवार ने इस खास पल को यादगार बनाया है।



मुकाबलों में दिल्ली की कप्तानी भी की। हालांकि 2025 मेगा ऑक्शन से पहले तस्क रफू के साथ कुछ मतभेदों के बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया था।

इस ट्रेड में कुलदीप दिल्ली कैपिटल्स का साथ छोड़कर लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल हो गए हैं। कुलदीप का दिल्ली के साथ 5 सीजन का एक बेहद सफल सफर रहा है,

जो अब इस ट्रेड के साथ समाप्त हो गया है। कुलदीप साल 2022 में दिल्ली की फ्रेंचाइजी से जुड़े थे। तब से लेकर अब तक उन्होंने टीम के लिए 65 मैचों में 72 विकेट अपने नाम किए हैं। यह बदलाव कुलदीप के लिए भी एक तरह से घर वापसी का संकेत है। उन्होंने घरेलू क्रिकेट उत्तर प्रदेश से खेला है, जबकि पंत दिल्ली के खिलाड़ी रहे हैं।

स्पेस में भी फीफा वर्ल्ड कप का खुमार:'ट्रिऑंडा' बॉल से फुटबॉल खेलते दिखे नासा के अंतरिक्ष यात्री

फीफा विश्व कप 2026 के बीच

अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों ने फुटबॉल खेला है जिसका वीडियो सामने आया है। नासा के अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर, क्रिस विलियम्स, जैक हैथवे और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) की अंतरिक्ष यात्री सोफी एडेनोट ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) में फुटबॉल खेलकर फीफा वर्ल्ड कप सेलिब्रेट किया। वीडियो में अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में तीन अलग-अलग फुटबॉल घूमते हुए दिखे। अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा, 'आप चाहे किसी भी टीम का समर्थन करें, पूरे दिल से चीयर करें। हम यहां ऊपर तक आपका उत्साह सुनना चाहते हैं।' ट्रिऑंडा को खेल सामान बनाने वाली कंपनी एडिडास ने तैयार किया है। फीफा के



अनुसार, इसका नाम स्पेनिश भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ तीन लहरें होता है। यह नाम इसलिए चुना गया क्योंकि 2026 का वर्ल्ड कप पहली बार तीन देशों कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में खेला जा रहा है। गेंद में लाल, हरा और नीला रंग इस्तेमाल किया गया है, जो इन तीनों

देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी बनावट भी खास है, जिसमें चार पैनल मिलकर एक त्रिकोणीय आकार बनाते हैं, गेंद में गहरे सीम और उभरी हुई सतह दी गई है, जिससे वायुरश या गीले मौसम में भी खिलाड़ियों को बेहतर पकड़ मिलती है और गेंद की उड़ान अधिक स्थिर रहती है।

धार हादसों का शहर है, युवक की हुई मौत? हादसे के बाद भी नहीं जागे जिम्मेदार! आखिर प्रशासन कब जागेगा?

अतिक्रमण की भेंट चढ़ी आदर्श सड़क, फुटपाथ बने स्थायी सब्जी बाजार

हादसों में जा रही बेकसूर लोगों की जान
राकेश साहू

धार। शहर की एकमात्र आदर्श सड़क मोहन टाकीज चौराहे से त्रिमूर्ति चौराहे तक आज अस्थाई बाजार बन चुका है, यह आदर्श सड़क अतिक्रमण की गंभीर समस्या से जूझ रही है। जिस सड़क को शहर की सुंदरता, स्वच्छता और सुव्यवस्थित यातायात की पहचान माना जाता था, वह आज स्थायी सब्जी मंडी और अवैध कब्जों का केंद्र बन गई है। दोनों ओर फुटपाथों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण होने से पैदल चलने वाले लोगों, विद्यार्थियों, बुजुर्गों और महिलाओं को अपनी जान जोखिम में डालकर फुटपाथ पर न चलते हुए सड़क पर चलना पड़ रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार एक परिवार के कई सदस्यों ने वर्षों से फुटपाथों पर कब्जा जमा रखा है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने कब्जाई गई जगहों को किराए पर देना भी शुरू कर दिया है। कई स्थानों पर 20 से 25 फीट तक सड़क और फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण कर स्थायी दुकानें संचालित की जा रही हैं।

फुटपाथ पैदल यात्रियों के लिए होते हैं, कब्जे के लिए नहीं

शहर के प्रमुख मार्गों पर फुटपाथ पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, लेकिन वर्तमान में वहां सब्जी, फल और अन्य



अस्थायी दुकानों का स्थायी बाजार खड़ा हो चुका है। मजबूरी में लोग सड़क पर चल रहे हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। अतिक्रमण के कारण वाहन चालक बीच सड़क पर वाहन खड़े कर खरीदारी करने चले जाते हैं। इससे यातायात बाधित होता है और रांग साइड से आने-जाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।

युवक की हुई अकाल मौत!

आदर्श सड़क पर पोस्ट ऑफिस के सामने रांग साइड से आने जाने में बाड़क और टेम्पो वाहन की टक्कर में महेश पिता कनसिंह डोडवे 20 वर्ष, निवासी मनावर, गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रांग साइड से आवागमन भी हादसे का

एक बड़ा कारण माना जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते अतिक्रमण हटाया जाता और यातायात व्यवस्था सुधारी जाती, तो कई दुर्घटनाओं को रोका जा सकता हैं।

नपा की योजनाएं अधूरी, गुमटियां सड़कर नष्ट हो गईं

जिला प्रशासन द्वारा इंदौर नाके स्थित राजा भोज उद्यान क्षेत्र में सब्जी मंडी विकसित की गई हैं, उक्त क्षेत्र में सब्जी मंडी नहीं लगाई जाती। इसके अलावा मोदी पेट्रोल पंप के सामने फल विक्रेताओं के लिए नगर पालिका ने गुमटियां बनाकर नीलामी और पंजीयन भी किए गए थे, लेकिन इन योजनाओं को धरातल पर लागू नहीं किया गया। परिणामस्वरूप सड़क



किनारे अवैध बाजार लगातार फैलता गया।

शहर के प्रमुख चौराहों पर यातायात सिग्नल की आवश्यकता

इंदौर नाका, त्रिमूर्ति चौराहा (पुराना सिग्नल लंबे समय से बंद) घोड़ा चौपाटी, डीपी ज्वेलर्स के सामने, जिला अस्पताल के सामने, मोहन टाकीज चौराहा इन स्थानों पर भारी यातायात दबाव रहता है और सिग्नल व्यवस्था नहीं होने से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।

बस स्टैंड पर भी अव्यवस्था चरम पर

बस स्टैंड क्षेत्र में भी अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग की बड़ी समस्या बनी हुई

है। बस संचालक सड़क किनारे बसें खड़ी कर सवारियों का इंतजार करते हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है।

माननीय न्यायालय और प्रशासन के नियम क्या कहते हैं?

भारत के उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों ने कई बार स्पष्ट किया है कि फुटपाथों का प्राथमिक अधिकार पैदल यात्रियों का है। सार्वजनिक सड़क और फुटपाथ पर स्थायी अतिक्रमण अवैध है। नगर निकाओं और प्रशासन का दायित्व है कि वे नियमित रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। पुनर्वास की व्यवस्था होने पर व्यवस्थित स्थानों पर

व्यवसायियों को स्थानांतरित किया जाए। सड़क सुरक्षा और आम नागरिकों के जीवन की रक्षा प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

प्रशासन को क्या करना चाहिए?

मोहन टाकीज चौराहे से त्रिमूर्ति चौराहे तक विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाए। फुटपाथ पूरी तरह पैदल यात्रियों के लिए मुक्त कराए जाएं।सब्जी एवं फल विक्रेताओं को निर्धारित मंडियों और गुमटियों में स्थानांतरित किया जाए। प्रमुख चौराहों पर यातायात सिग्नल तत्काल लगाए जाएं।बस स्टैंड क्षेत्र में पार्किंग और बस संचालन की व्यवस्था तय की जाए। रांग साइड चलने वालों और अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई की जाए। स्वच्छता और यातायात व्यवस्था की संयुक्त निगरानी नगर पालिका और यातायात विभाग करें।

बड़ा सवाल यह है कि बेकसूर लोगों की मौतों का जिम्मेदार कौन?

जब अतिक्रमण वर्षों से मौजूद है, योजनाएं बनीं लेकिन लागू नहीं हुईं, यातायात सिग्नल बंद पड़े हैं और फुटपाथ कब्जे में हैं, तो आखिर इन हादसों की जिम्मेदारी किसकी होगी? जिला प्रशासन, नगर पालिका और यातायात विभाग को अब गंभीरता से कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा शहर की यह आदर्श सड़क लगातार हादसों और अकाल मौतों की सड़क बनती जाएगी।

अग्निवीर बन घर लौटा बेटा भावुक माँ ने लगाया गले

बकरवाहा। क्षेत्र के एक होनहार युवक ने अग्निवीर में चयनित होकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। छह माह की ट्रेनिंग पूर्ण कर जब युवक अपने गांव लौटा तो बस स्टैंड पर भावुक मांहील देखने को मिला। माँ ने बेटे को गले लगाकर स्वागत किया, वहीं परिवारजनों,



हरि सिंह यादव, पिता स्व. छोटे लाल यादव, ने शासकीय नवीन महाविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में

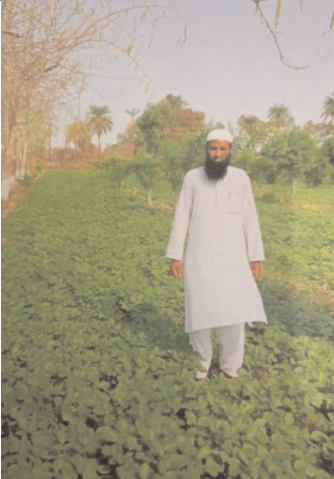
रखते हुए उन्होंने बिना किसी कोशिश के घर से ही ऑनलाइन माध्यम से अग्निवीर भर्ती की तैयारी शुरू की और अपने दृढ़ संकल्प व मेहनत के बल पर सफलता हासिल कर परिवार का नाम गौरवान्वित किया। हरि सिंह यादव ने बताया कि अग्निवीर भर्ती की परीक्षा, फिजिकल, मेडिकल और मेरिट सूची के चारों चरणों में सफलता प्राप्त करने के बाद उन्हें आर्मी परपत्र डिफेंस सेंटर, उड़ीसा में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूर्ण कर छह माह बाद जब वे अपने गांव लौटे तो गांव की मिट्टी में कदम रखते ही बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और छोटों का स्नेह देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। हरि सिंह ने अपनी सफलता का श्रेय स्वर्गीय पिता की मेहनत, गुरुजनों से मिली शिक्षा, बड़े-बुजुर्गों के आशीर्वाद, माँ, भाई-बहनों तथा परिजनों के प्रेम और सहयोग को दिया। उन्होंने युवाओं से कठिन परिश्रम, अनुशासन और लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का संदेश देते हुए कहा कि निरंतर प्रयास करने वालों को सफलता अवश्य मिलती है।

जैविक खेती के प्रेरणास्रोत कृषक मजीद खान सफलता की कहानी

माधो सिंह दांगी

भोपाल। भोपाल जिले के इमलिया नरेन्द्र गांव के प्रगतिशील कृषक मजीद खान ने अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पण से जैविक खेती के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने स्वेच्छा से जैविक खेती को अपनाया और पिछले एक दशक से अनेक चुनौतियों के बावजूद निरंतर इस पद्धति पर कार्य कर रहे हैं। उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उन्हें उत्तम कृषक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जब बड़े शहरों में भी जैविक उत्पादों की स्वीकार्यता को लेकर संदेह बना हुआ था, तब मजीद खान ने अपनी मेहनत और विश्वास के बल पर एक अलग पहचान बनाई। वर्ष 2019 में उन्होंने मध्यप्रदेश जैविक प्रमाणीकरण संस्था से अपने फल एवं सब्जियों का पंजीकरण कराया। आज वे भोपाल के नागरिकों को जैविक रूप से उत्पादित ताजी सब्जियां, फल और फूल उपलब्ध करा रहे हैं।

मजीद खान लगभग 8 एकड़ भूमि पर जैविक खेती करते हैं। प्रारंभिक वर्षों में उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ा। कई लोगों ने उन्हें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से कभी समझौता नहीं किया। उन्हें प्राकृतिक खेती की प्रेरणा कृषि विभाग के पूर्व संचालक एवं प्रकृतिविद डॉ.



जी.एस. कौशल से प्राप्त हुई। वर्ष 2015 से उन्होंने गाय के गोबर, गोमूत्र से निर्मित जीवामृत, वर्मी कम्पोस्ट, नाडेप खाद तथा फसल अवशेषों से तैयार जैविक खाद का उपयोग शुरू किया। धीरे-धीरे उनके खेतों में रासायनिक खाद की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त हो गई। इसके परिणामस्वरूप मिट्टी की उर्वरता बढ़ी, फसलों की गुणवत्ता में सुधार हुआ तथा मल्टिप्लिंग और कम सिंचाई के कारण जल संरक्षण भी संभव हुआ।

उनकी सफलता से प्रेरित होकर आसपास के अनेक किसानों ने भी जैविक एवं प्राकृतिक खेती अपनाना शुरू किया। वर्तमान में जिले में 1200 से अधिक किसान प्राकृतिक एवं जैविक खेती कर रहे हैं। मजीद खान स्वयं भी किसानों को प्रशिक्षण और प्रेरणा देकर इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका

मानना है कि खेती को पूरी तरह प्राकृतिक और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से किया जाना चाहिए। खेती में वे वर्मी कम्पोस्ट, गोबर खाद, फसल अवशेष, मल्टिप्लिंग तथा छछ आधरित जैविक घोल का उपयोग करते हैं। इन उपायों से वे कीट एवं रोगों का प्रभावी नियंत्रण करते हैं और रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। विविधतापूर्ण खेती और नवाचारों के कारण उन्होंने एक सफल एवं अनुरकणीय मॉडल विकसित किया है। लगातार दस वर्षों से रासायनिक खाद का उपयोग न करने के कारण उन्हें जैविक खेती का आधिकारिक पंजीकरण भी प्राप्त हो चुका है, जो उन्हें प्रदेश के चुनिंदा जैविक किसानों में शामिल करता है।

मजीद खान ने मनरेगा योजना के अंतर्गत जल संरक्षण और पशुपालन को भी अपनी खेती से जोड़ा है। उन्होंने बलराम कूप का निर्माण कर वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की तथा ड्रिप सिंचाई के माध्यम से कम पानी में अधिक उत्पादन सुनिश्चित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनरेगा के तहत 30म12 मीटर का पशु शेड बनवाया और ध्यानिकी विभाग से प्राप्त 500 आम, मुनगा, अमरूद, नींबू और जामुन के पौधों का रोपण किया। मजीद खान की यह यात्रा दर्शाती है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, नवाचार और प्रकृति के प्रति समर्पण से खेती को लाभकारी, टिकाऊ और पर्यावरण हितैषी बनाया जा सकता है। उनकी सफलता अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और जैविक खेती के बढ़ते महत्व को भी रेखांकित करती है।

तीन दिन में बदल गई कार्रवाई की कहानी, अवैध रेत मामले में मामला ओवरलोडिंग में सिमटा

कौन बचा रहा था रेत के माफिया को ? तीन दिन बाद खुली नई कहानी

जुगल मिश्रा

शहडोल। जैतपुर-बुढ़ार मार्ग पर अवैध रेत परिवहन के खिलाफ हुई राजस्व विभाग की कार्रवाई अब खुद सवालों के घेरे में आ गई है। बता दें कि, जिस मामले में एसडीएम जैतपुर को टीम में से भरे तीन हाइवा वाहनों को पकड़कर बड़ी कार्रवाई की थी, उसी मामले में अब जो जानकारी सामने आ रही है कि, दो वाहनों को केवल ओवरलोडिंग का चालान काटकर सोमवार को छोड़ दिया गया है। इसके बाद पूरे घटनाक्रम को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं गौरतलब है कि, कार्रवाई के दौरान पकड़े गए दो हाइवा वाहन क्रमांक एमपी 18 जेडसी 3574 एवं एमपी 18 एच 5275 जिला पंचायत सदस्य जगन्नाथ शर्मा से संबंधित बताए गए थे। दोनों वाहनों को जब्त कर बुढ़ार थाना परिसर में रखा गया था। जबकि, तीसरा वाहन सीजी 10 बीक्यू 9862 मौके से रेत खाली करने के बाद वाहन सहित फरार हो गया था।

ये नहीं जब दस्तावेज, तो क्यों नहीं बना खनिज प्रकरण?

पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि, जब एसडीएम जैतपुर ने वाहनों को पकड़ा था, तब क्या वाहन चालकों से रेत परिवहन से

संबंधित दस्तावेजों की जांच नहीं की गई थी? यदि सभी दस्तावेज मौके पर उपलब्ध थे, तो वाहनों को तीन दिनों तक थाने में खड़ा रखने की आवश्यकता क्या थी? इस संबंध में हुई चर्चा के दौरान जैतपुर तहसीलदार आर.के. पद्माकर ने स्वीकार किया था कि, वाहनों में रेत परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया था कि, उक्त मामला रेत चोरी और ओवरलोडिंग का है। यदि यह बात सही है, तो फिर खनिज विभाग को सूचना देकर खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अवैध खनिज परिवहन के मामले में जुर्मना अधिरोपित करने और प्रकरण दर्ज करने की प्रक्रिया आखिर क्यों नहीं अपनाई गई?

ओवरलोडिंग थी तो तौल कहाँ हुई?

बताया जा रहा है कि, वाहनों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केवल ओवरलोडिंग का मामला बनाकर छोड़ा गया है। लेकिन, यहां भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि वाहन ओवरलोड थे, तो क्या उनका अधिकृत कांटे पर वजन कराया गया? वाहन में कितनी मात्रा में सामग्री ओवरलोड थी? उसका कोई अभिलेख तैयार किया गया या नहीं?

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194 के तहत ओवरलोड पाए जाने पर अतिरिक्त सामग्री उतरवाकर उसका दस्तावेजीकरण किया जाना आवश्यक होता है। ऐसे में क्या अतिरिक्त रेत



उतरवाई गई? याद उतरवाई गई, ता उसका पंचनामा कहाँ है? यदि नहीं उतरवाई गई तो कार्रवाई किस आधार पर की गई?

तीन दिन तक थाने में क्यों खड़े रहे वाहन?

यदि मामला केवल ओवरलोडिंग का था, तो चालान बनाकर तत्काल कार्रवाई की जा सकती थी। फिर वाहनों को तीन दिनों तक थाना परिसर में रखने का औचित्य क्या था? यह प्रश्न भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सूत्रों का दावा है कि, इस दौरान संबंधित पक्ष को दस्तावेजों की व्यवस्था करने का पर्याप्त समय मिला। चर्चा यह भी है कि, छत्तीसगढ़ से उस दिनांक के ट्रॉजिट पास की व्यवस्था कर मामले को सामान्य मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई तक सीमित कर दिया गया है।

पुराना इतिहास भी सवालों के घेरे में

इस मामले को लेकर इसलिए भी चर्चाएं

तेज हैं, क्योंकि जगन्नाथ शर्मा का नाम पूर्व में भी रेत और खनिज परिवहन से जुड़े विवादों में सामने आता रहा है। सूत्रों के अनुसार, अमलाई, बुढ़ार और खैरहा थानों में उनके खिलाफ विभिन्न मामलों में अपराध दर्ज हुए, जिनमें कई प्रकरण गंभीर धाराओं से संबंधित बताए जाते हैं। इतना ही नहीं, पूर्व में भी उनके नाम से जुड़े वाहनों पर कार्रवाई और जब्ती की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हाल ही में, बुढ़ार तहसीलदार ने उनके कब्जे वाली भूमि से लगभग 60 घनमीटर अवैध रेत की जब्ती की थी, यह कार्रवाई भी चर्चा में रही थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि, बचा-बार नाम सामने आने के बावजूद, संबंधित मामलों में प्रभावी और स्थायी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है।

बुढ़ार पुलिस की भूमिका पर उठ रहे सवाल

पूरे घटनाक्रम में सबसे अधिक सवाल बुढ़ार पुलिस की भूमिका को लेकर उठ रहे हैं। राजस्व विभाग की कार्रवाई के बाद मामला खनिज अपराध की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा था। लेकिन, अंततः यह केवल ओवरलोडिंग के चालान तक सीमित रह गया। स्थानीय जानकारों का कहना है कि, यदि रेत परिवहन के वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, तो मामला सीधे खनिज अधिनियम के तहत बनना चाहिए था।

ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि, कार्रवाई की दिशा अचानक कैसे बदल गई।

राजनीतिक संरक्षण की चर्चा

मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। जगन्नाथ शर्मा भाजपा के सक्रिय सदस्य माने जाते हैं। क्षेत्र में यह चर्चा है कि, उनके बचाव में संगठन के कुछ प्रभावशाली पदाधिकारी भी सक्रिय हुए। अब यह सवाल लगातार उठ रहा है कि, क्या एक संभावित खनिज अपराध का मामला प्रशासनिक और राजनीतिक प्रभाव के कारण महज ओवरलोडिंग के चालान तक सीमित कर दिया गया है!

जवाब अब प्रशासन को देना है

पूरे घटनाक्रम के बाद अब प्रशासन और संबंधित विभागों को कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब देने होंगे। आखिर जब्ती के समय रेत परिवहन के वैध दस्तावेज मौजूद थे या नहीं? यदि दस्तावेज नहीं थे, तो खनिज विभाग को सूचना देकर खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यदि मामला केवल ओवरलोडिंग का था, तो वाहनों का वजन किस कांटे पर कराया गया और ओवरलोड सामग्री की मात्रा कितनी पाई गई? मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त सामग्री उतरवाई गई थी, या नहीं, और यदि उतरवाई गई थी, तो उसका रिकॉर्ड कहाँ है? इसके अलावा वाहनों को तीन दिनों तक थाना परिसर में रखने का कारण क्या था और बाद में प्रस्तुत किए गए

दस्तावेजों की सत्यता का परीक्षण किस स्तर पर किया गया?

प्रशासन की निष्पक्षता और कार्यप्रणाली की परीक्षा बना प्रकरण

इन सभी सवालों के स्पष्ट जवाब सामने आने तक पूरे मामले को लेकर संदेह और चर्चाओं का दौर जारी रहना स्वाभाविक है। राजस्व विभाग की कार्रवाई से शुरू हुआ यह मामला, अब केवल अवैध रेत परिवहन तक सीमित नहीं रह गया है। बल्कि, कार्रवाई की प्रक्रिया, विभागीय समन्वय और प्रभावशाली लोगों के प्रति प्रशासनिक रवैये पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर रहा है। शहडोल जिले में खनिज अपराधों को लेकर पहले से मौजूद चिंताओं के बीच यह प्रकरण प्रशासन की निष्पक्षता और कार्यप्रणाली की भी परीक्षा बन गया है।

इनका कहना है

वाहन छोड़ने का अधिकार वरिष्ठ अधिकारी एसडीएम साहब के अधिकार क्षेत्र का था। उन्होंने किन दस्तावेजों के आधार पर वाहनों को छोड़ा, यह वही बताएंगे।

आर के पद्माकर, नायब तहसीलदार, जैतपुर। वही वाहनों को छोड़े जाने संबंधित कार्रवाई की संपूर्ण जानकारी के लिए एसडीएम जैतपुर दीपक मंडवी को उनके मोबाइल पर कॉल किया गया, तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। जिसके चलते उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी है।